(XI) → शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार — 29-30

Cultural and Edutational Rights

Art 29 ⇒ अल्पसंख्यको अपनी भाषा, लिपि संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार.

⇒ Language, Script and culture]

Minorities ?

Minorities
↓
अल्पसंख्यक

= भारत के संविधान में अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया : Minorities ✓

↓
SC - ?

भाषा -
धर्म -
= ?

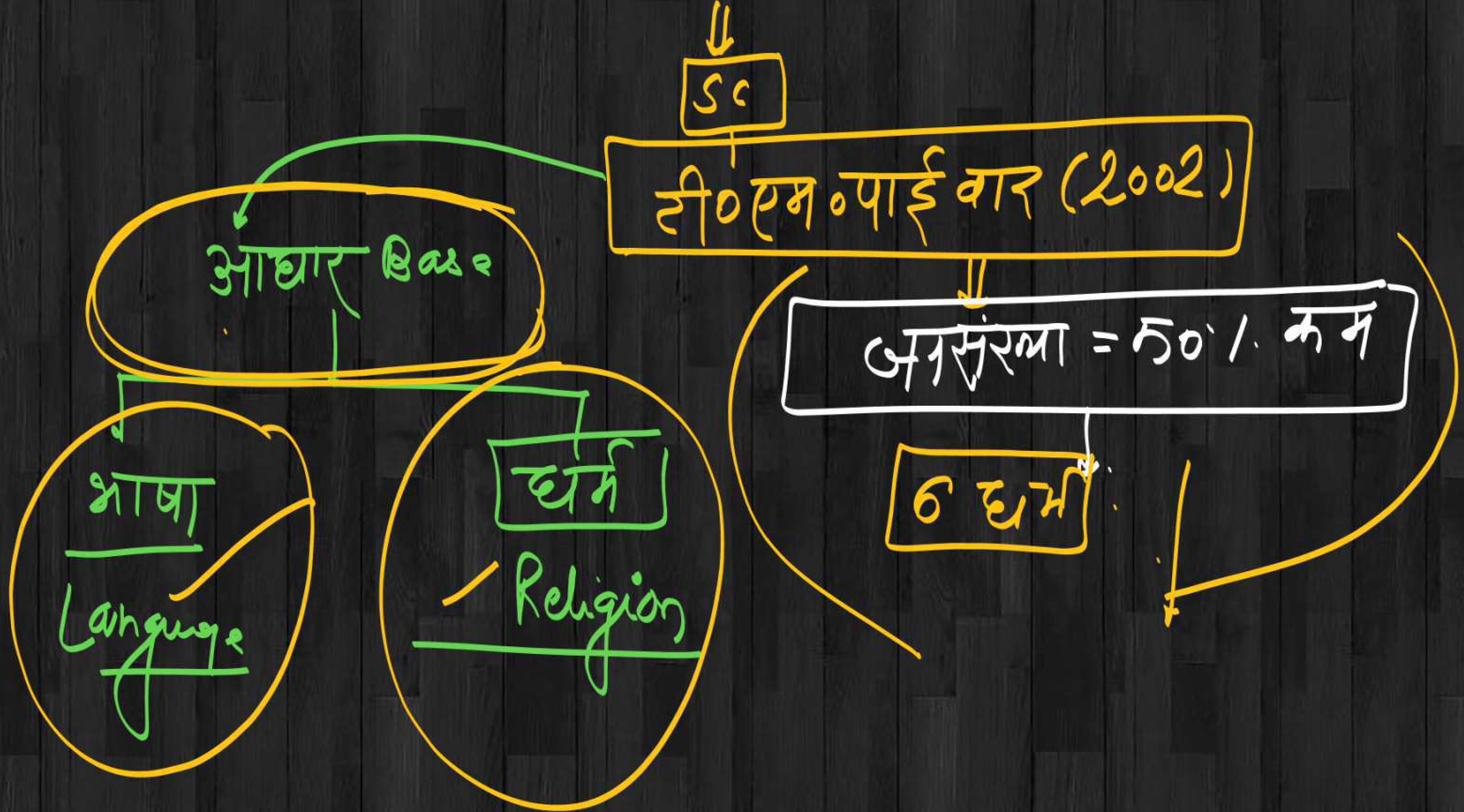
SC
टी०एम०पाई वाद (2002)
अल्पसंख्या = 50% कम
6 धर्म
आधार Base
भाषा
Language
धर्म
/ Religion

मुस्लिम ⇒ 14.30

जैन ⇒ 0.37%

बौद्ध 0.70%

सिख 1.72%

ईसाई 2.30%

पारसी 0.003%

अल्पसंख्यक

देश

हिन्दू (HINDU)

79.80

धर्म

Ah.

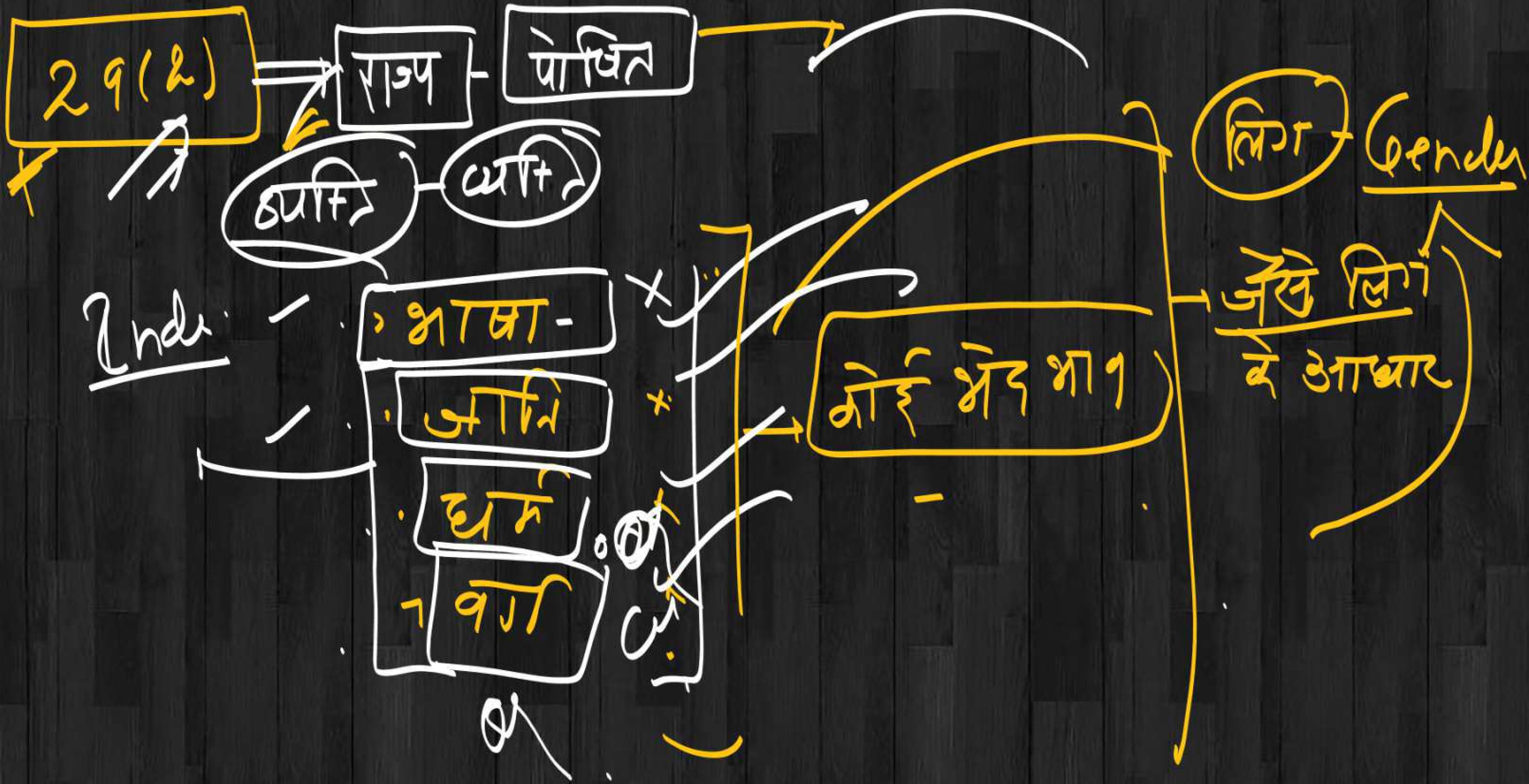
29(2)
राज्य
पोषित
भाषा
जाति
धर्म
वर्ग
कोई भेद भाव
लिंग
Gender
जैसे लिंग
के आधार

Art 30 ⟹ अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार। to open / Establishment

Affiliation – शिक्षा = syllabus + Aid

Affiliation + Aid = syllabus → Teacher → परीक्षा

No – No Aid

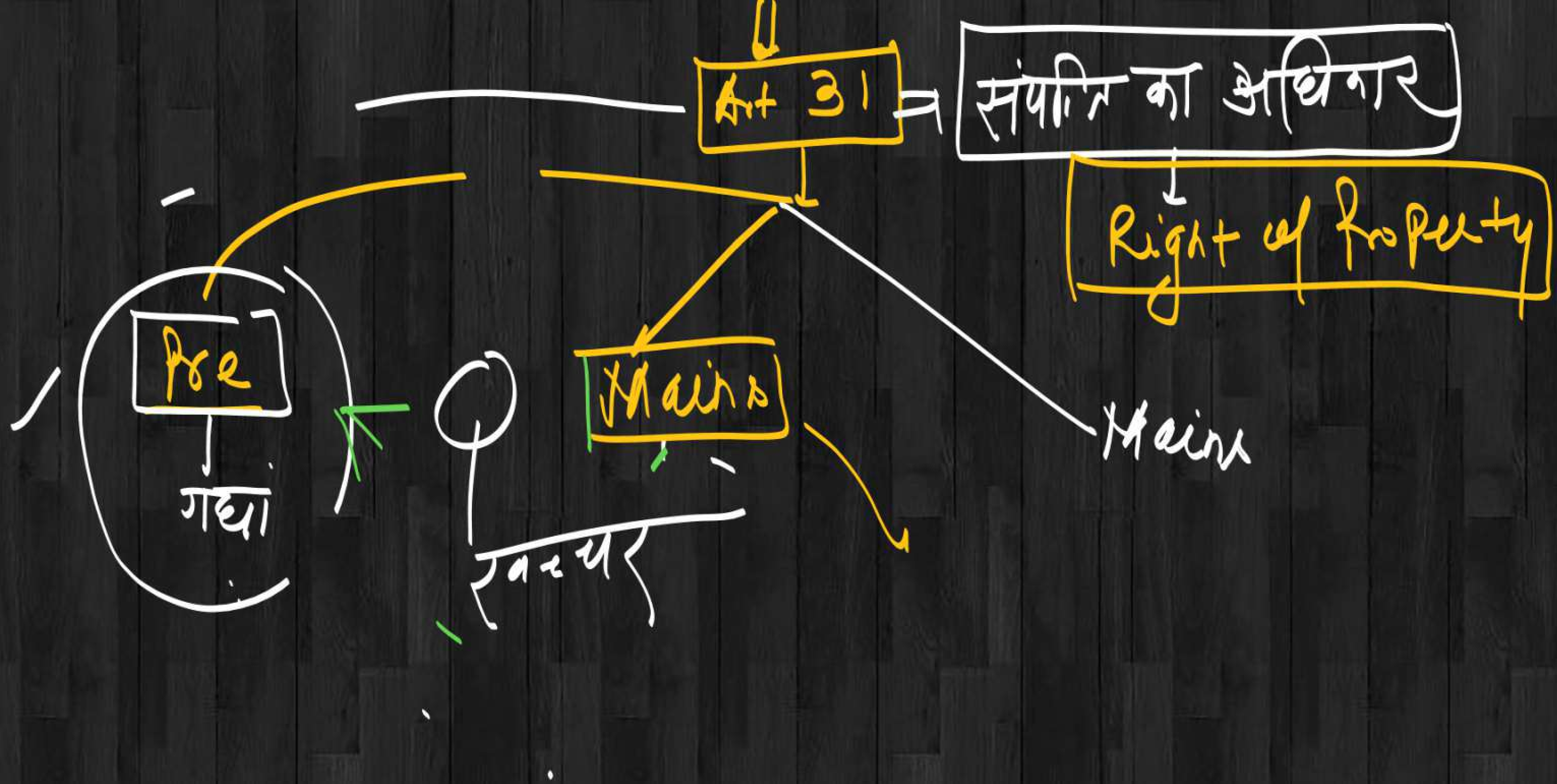

Art 31
संपत्ति का अधिकार
Right of Property
Pre
गधा
Mains
खच्चर
Mains

Art 31 - Right of Property

44वे संविधान संशोधन 1978 के माध्यम

Abolished by 44th Amendment 1978.

Art 300(A) - एक कानूनी अधिकार

Legal Right.

राज्य → संपत्ति पर नियंत्रण कर सकना

→ Control Private - Property

No - No ✗ → वाद । GFR

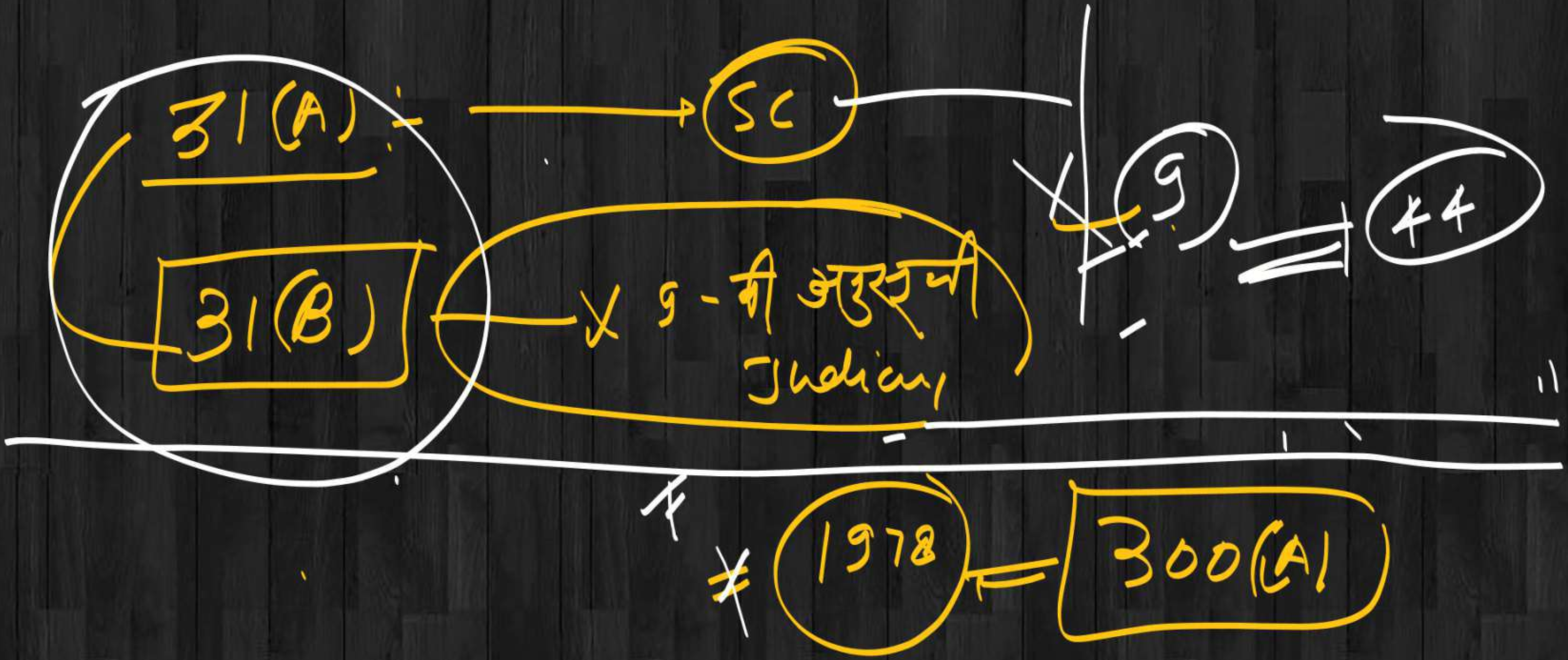
31(A) :-
SC
31(B)
X 9-वी अनुसूची
Judiciary
9
44
1978
300(A)

MCQ
Test

Art 32

Right of Constitutional Remedies

संविधानिक उपचारों का अधिकार

DR. B.R. Ambedkar

संविधान की आत्मा कहा

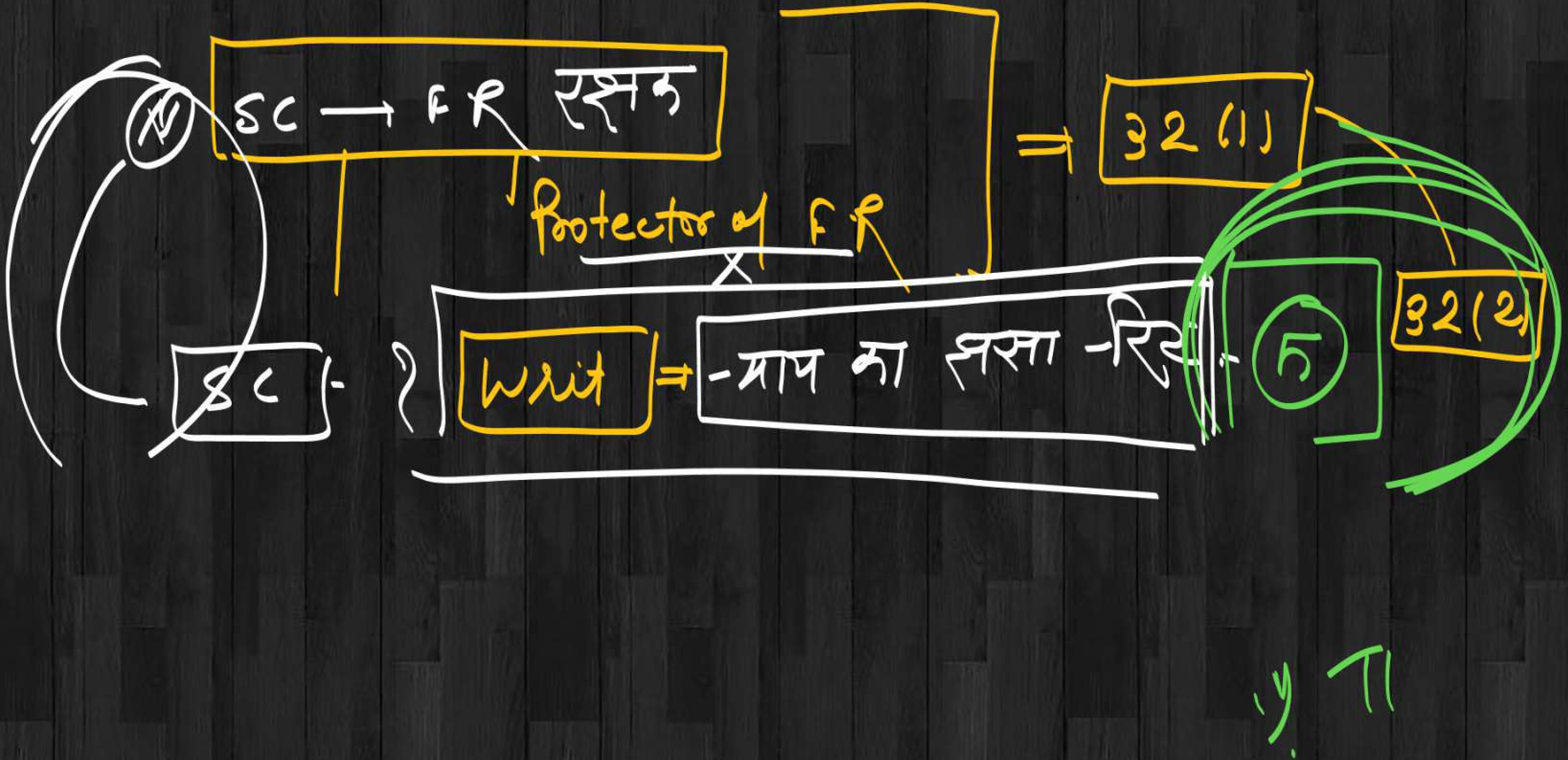

SC → FR रक्षक
Protector of FR
32 (1)
SC - ?
Writ ⇒ न्याय का रास्ता - रिट
5
32 (2)

— 32 (1) — SC

— 32 (2) — रिट

— 32 (3)

Parliament — संसद

कभी नहीं

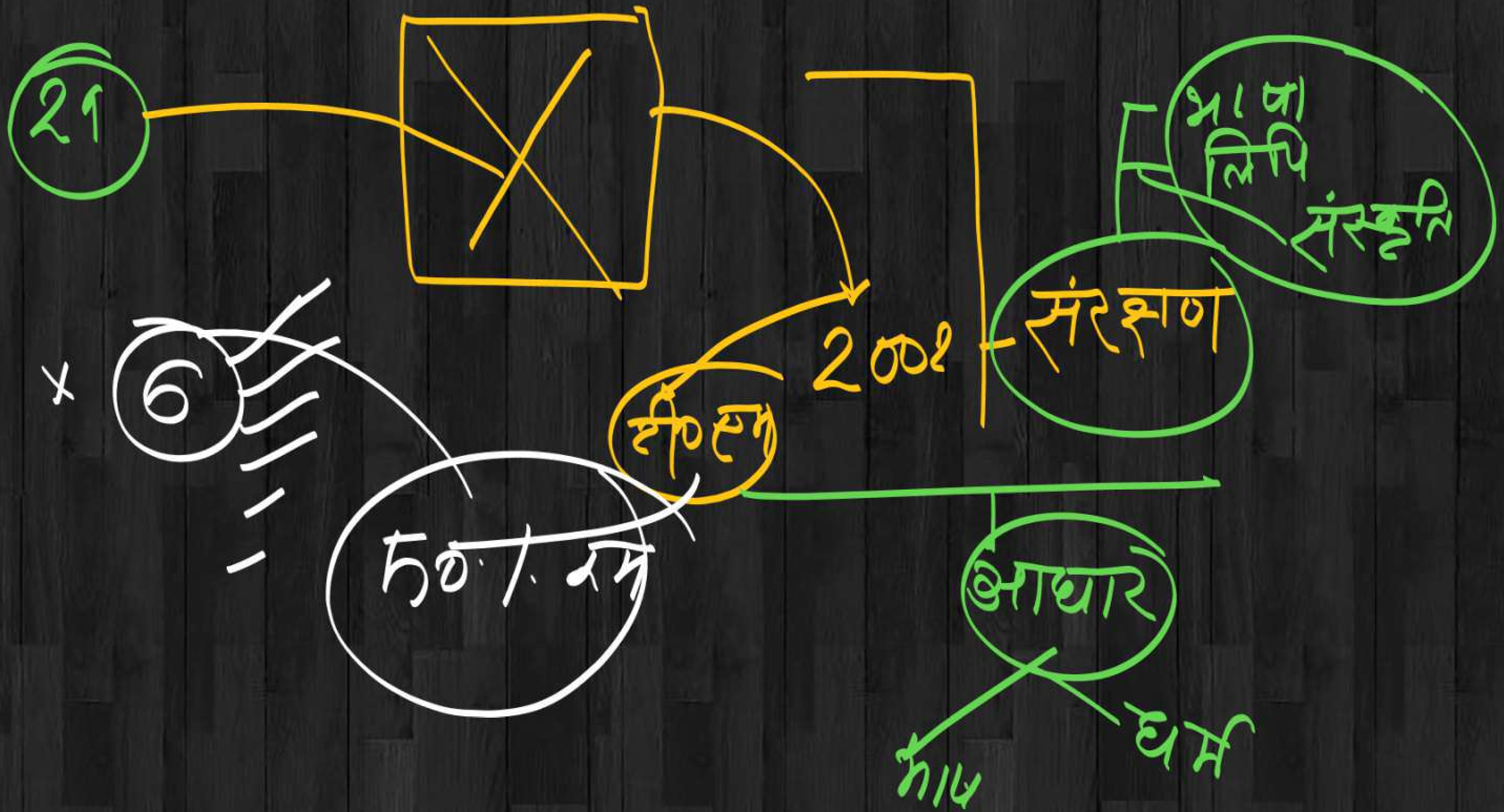
21
6
50%
2001
संरक्षण
भाषा
लिपि
संस्कृति
आधार
धर्म

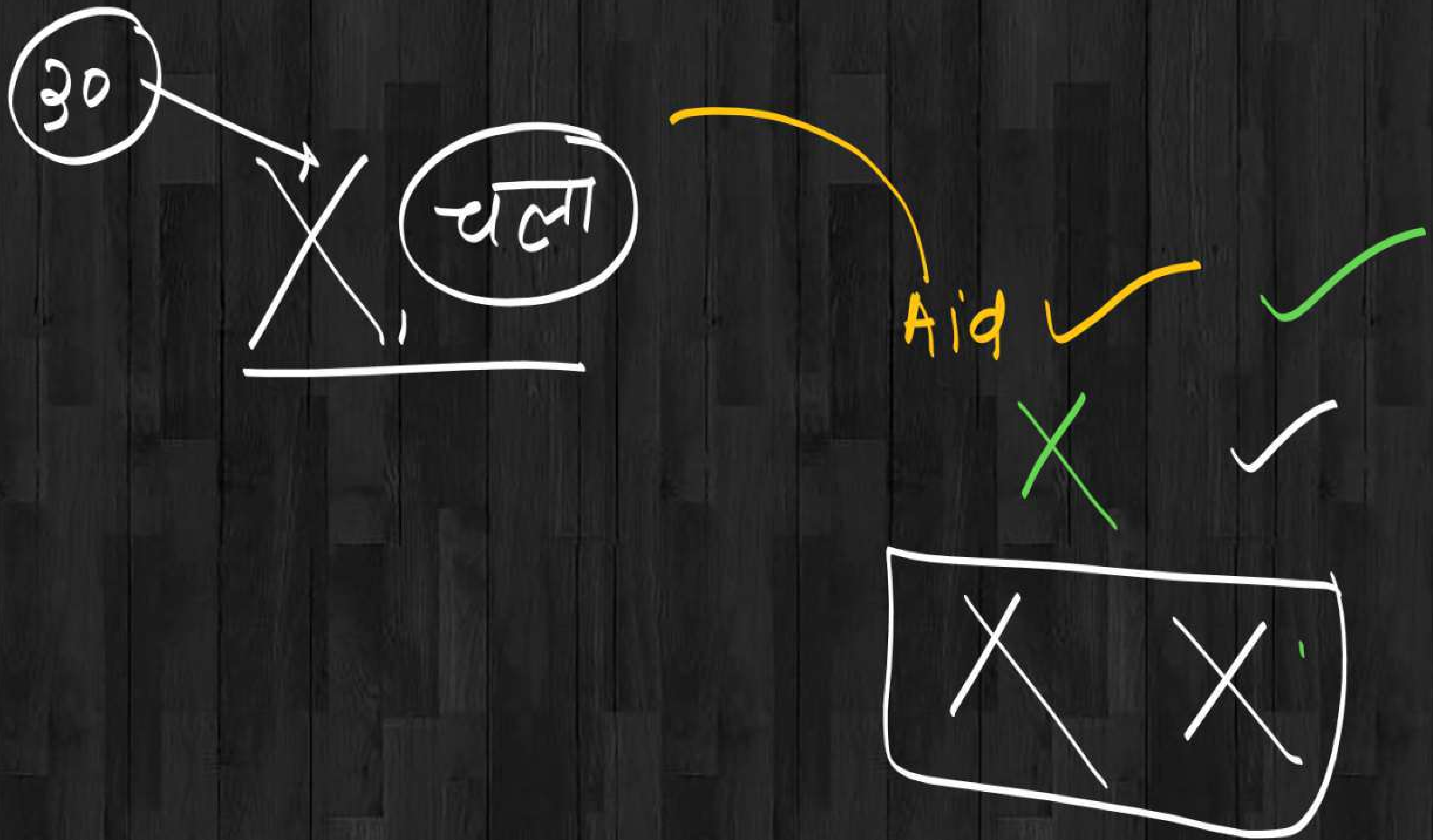
उ0
चला
Aid

31 ✗ —— 44 —— 1978 → 300(A)

SC ✗

↓

कानूनी अधिकार

31(A) ✓

31(B) → 9 ✗ —— है ✓

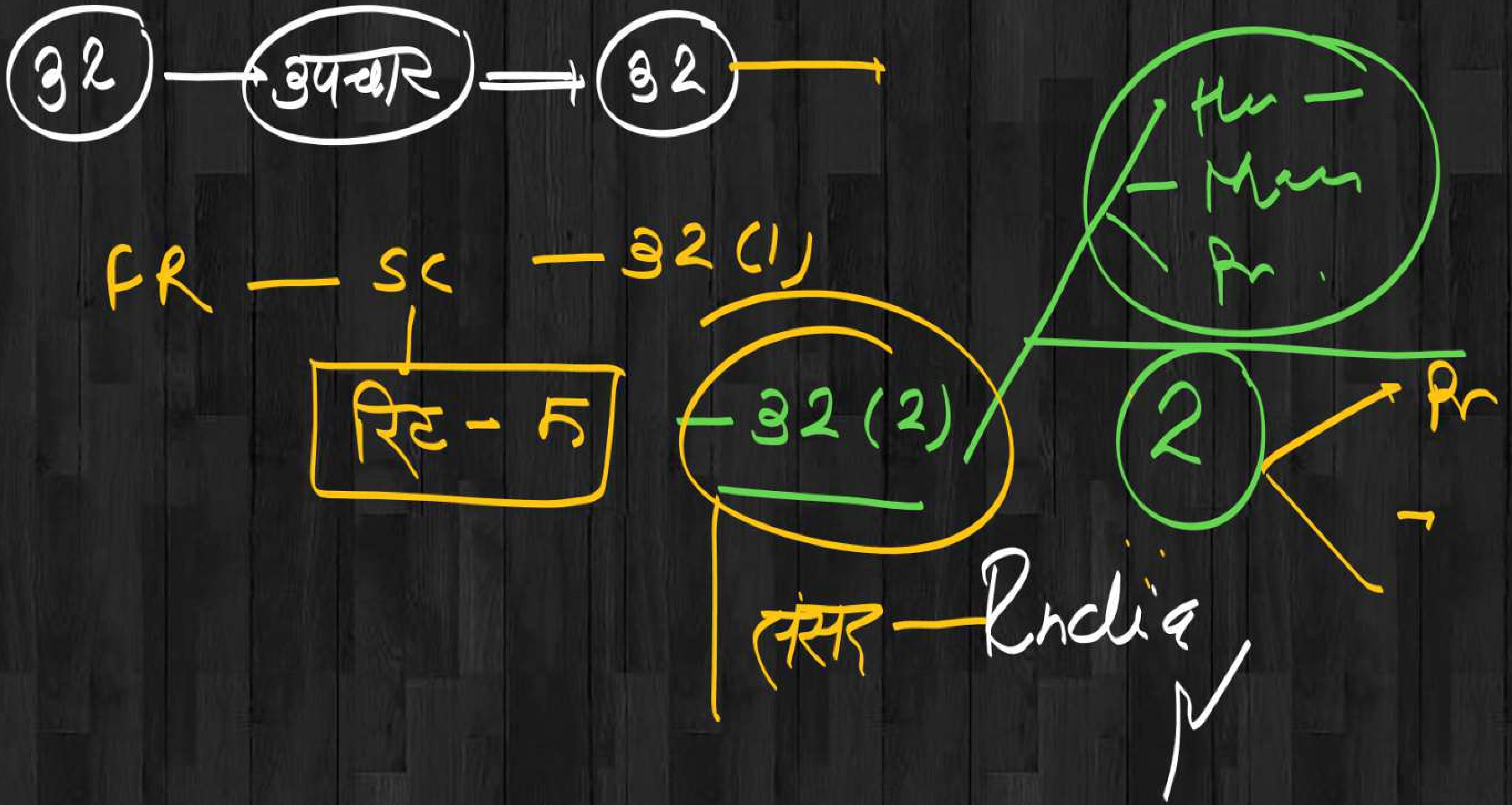
32
उपचार
32
FR
SC
32 (1)
रिट - 5
32 (2)
2
Pr

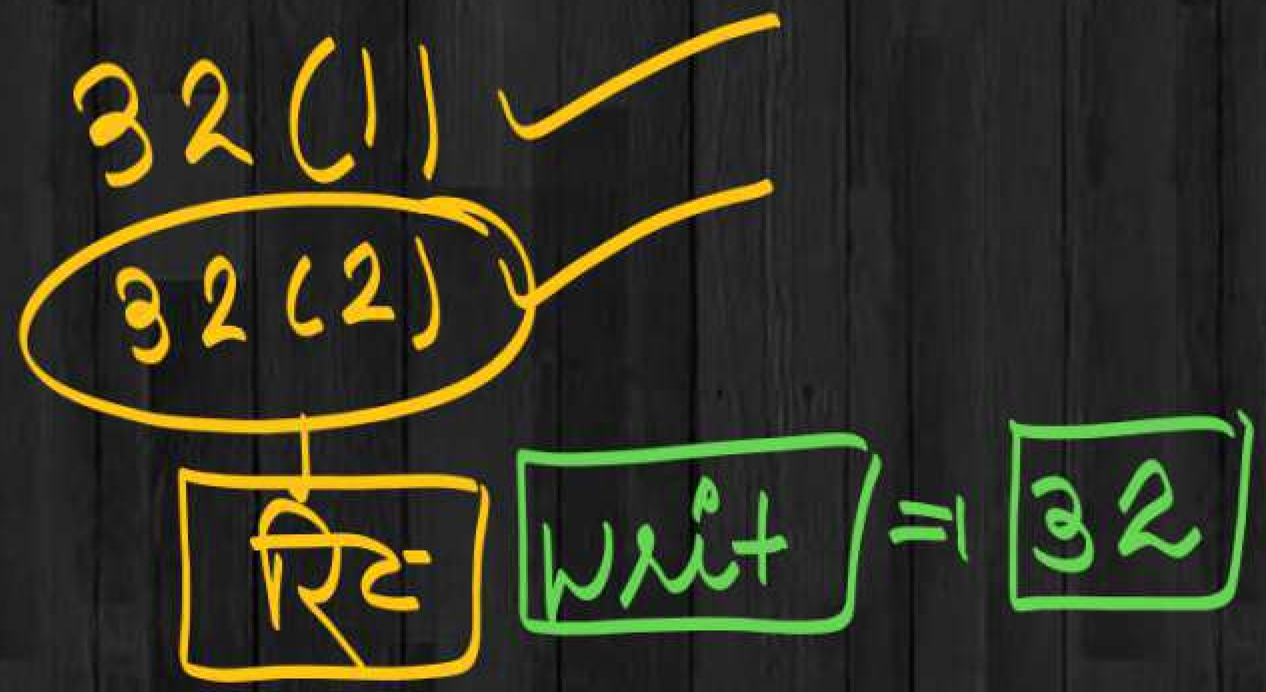
32(1)
32(2)
रिट
writ
= 32

(I) Mandmus ⟹ परमादेश

(II) Habeas Corpus ⇒ बंदी प्रत्यक्षीकरण

(III) Quo-Warranto ⇒ अधिकार-पृच्छा

(IV) Prohibition ⇒ प्रतिषेध

(V) Certiorari ⇒ उत्प्रेषण

लेख / आज्ञा

(i) Habeas Corpus :- बंदी प्रत्यक्षीकरण

शाब्दिक = अर्थ - Meaning

Bring the Body - 'सशरीर पेश करना'

जिंदा / मुर्दा

रिश्तेदार / मित्र

कोर्ट में

Against sate
any
an Individu

(ii) Mandmus - परमादेश

'Top Command'

We Command

हम आदेश देते हैं

'सर्वोच्च आदेश'

सरकारी

State - सरकार

Quo-Warranto – अधिकार पृच्छा

किस अधिकार से ?

What Authority ?

FIR =

Power / वैधता

SC

(iv) Prohibition

प्रतिषेध

SC

सिर्फ

रोक दे

Just STOP

HC

Certiorari

उत्प्रेषण

SC

HC

Just Transfer

STOP

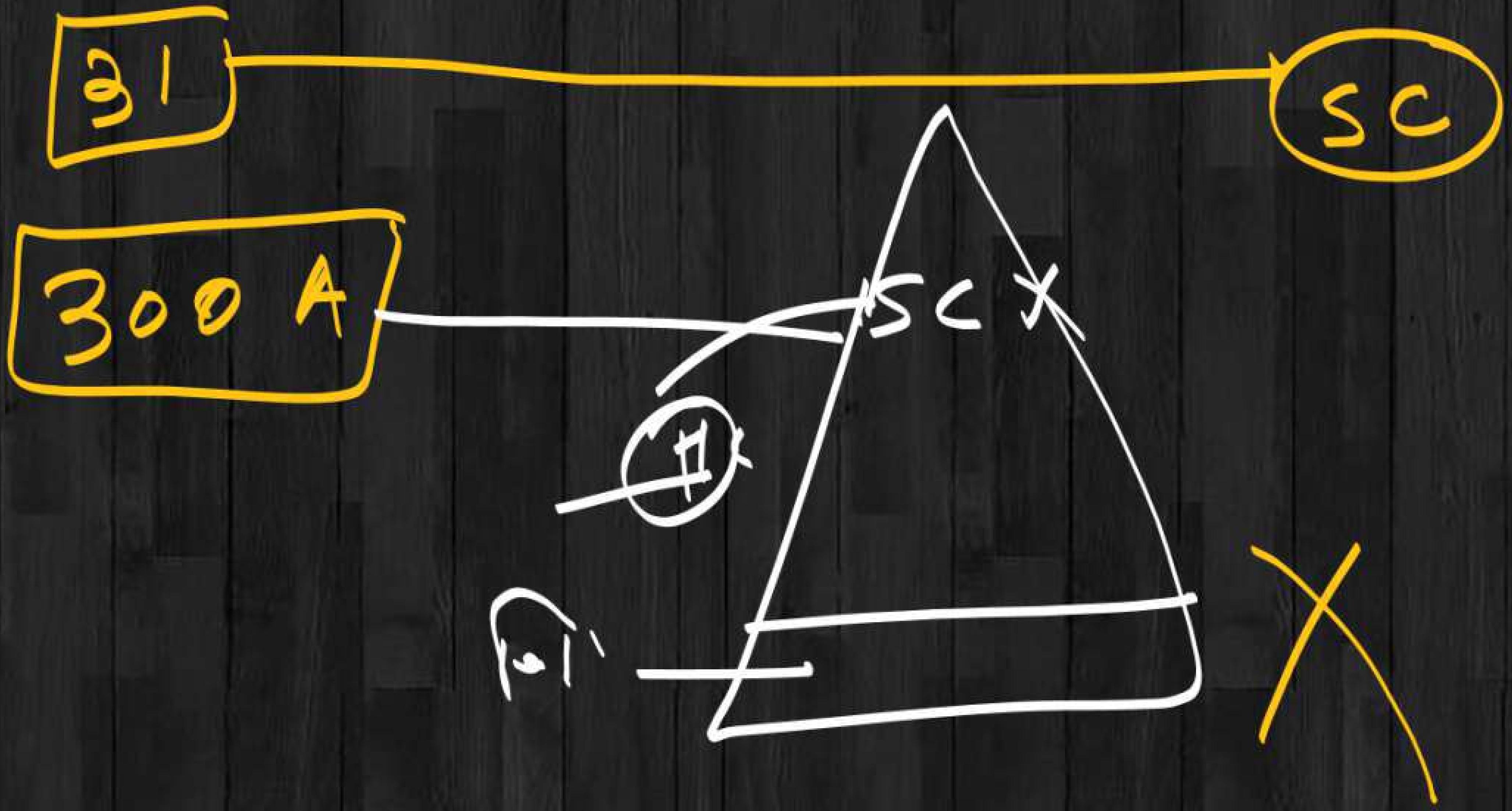
31
SC
300 A
SC X
X

POLITY

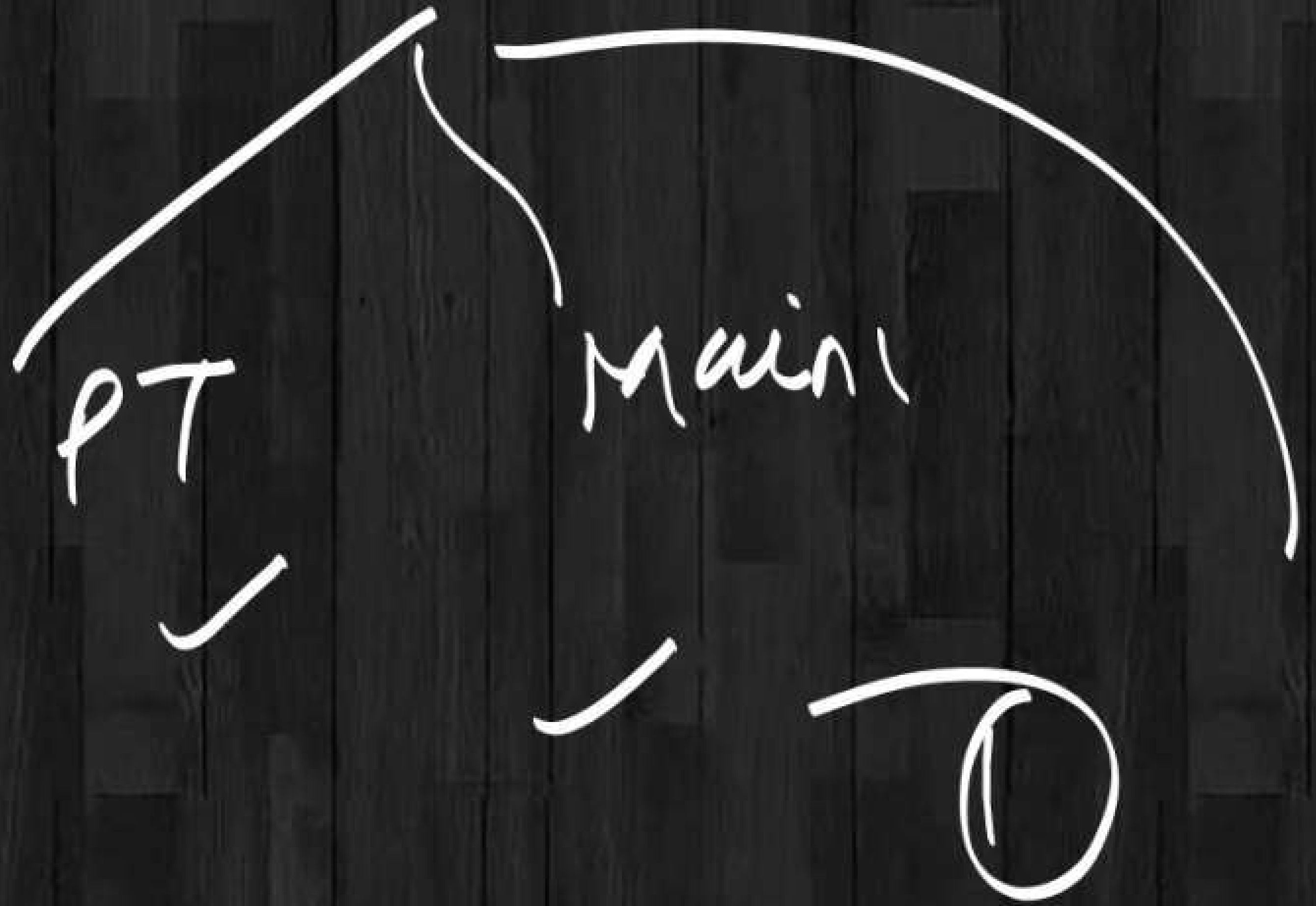
PT
Maini

200
+
100

UPSC —

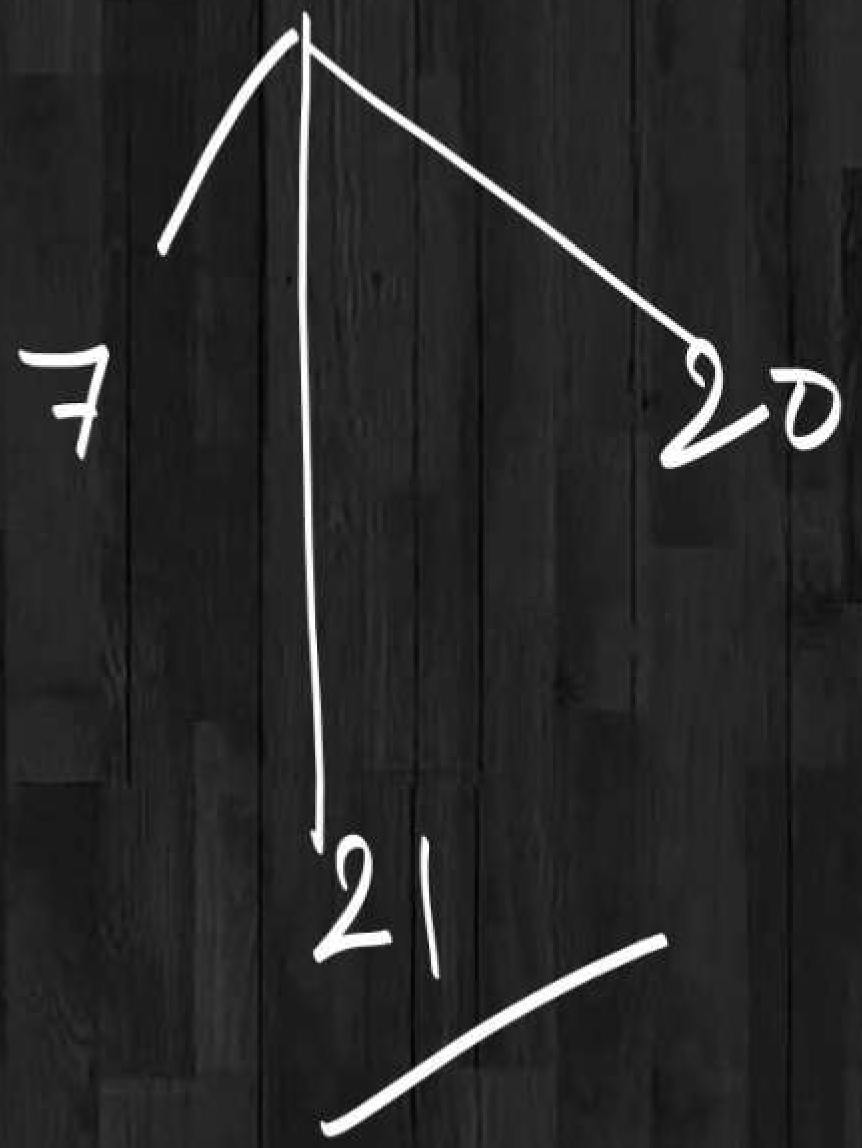
7
20
21

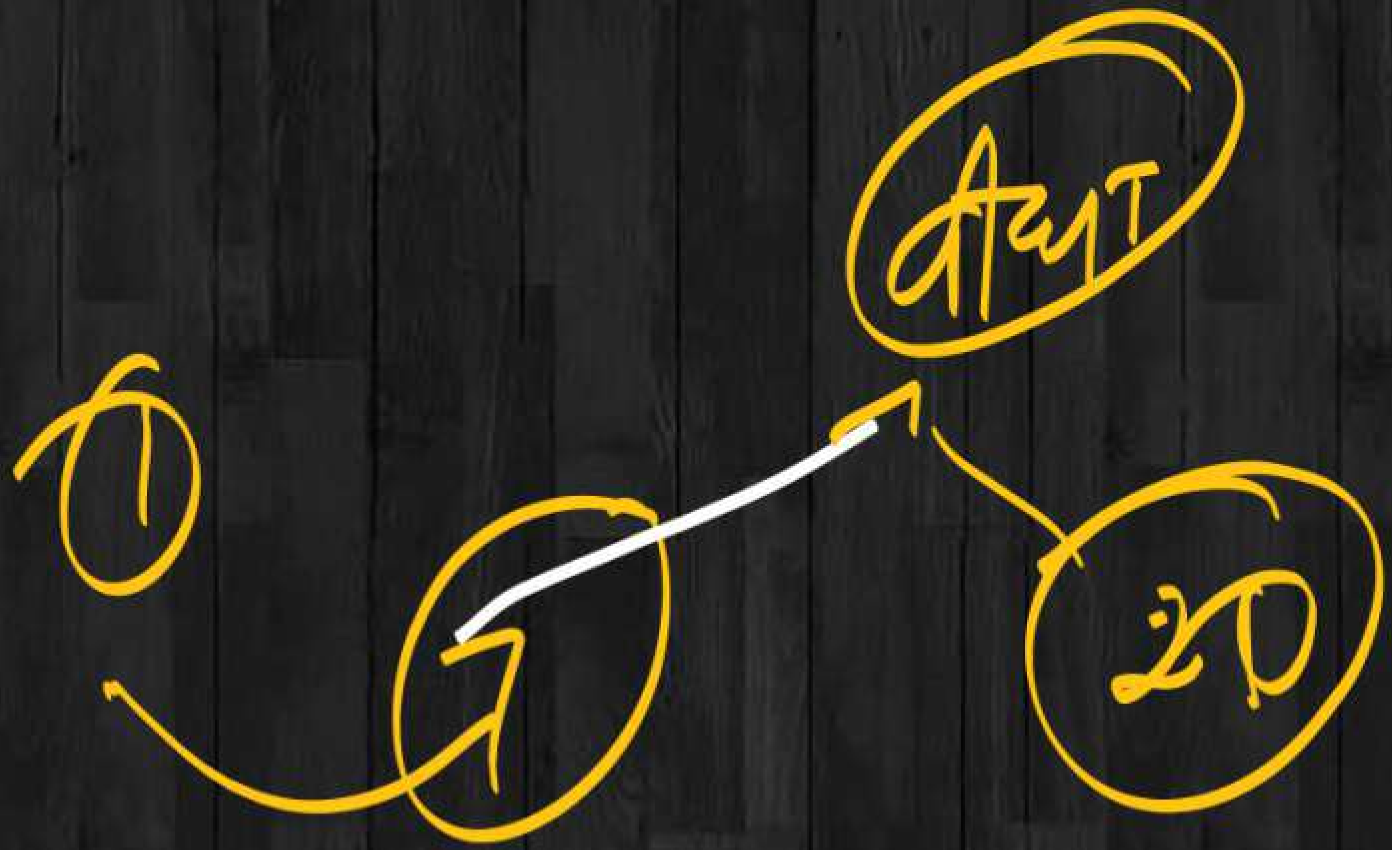

स्थिर

100.

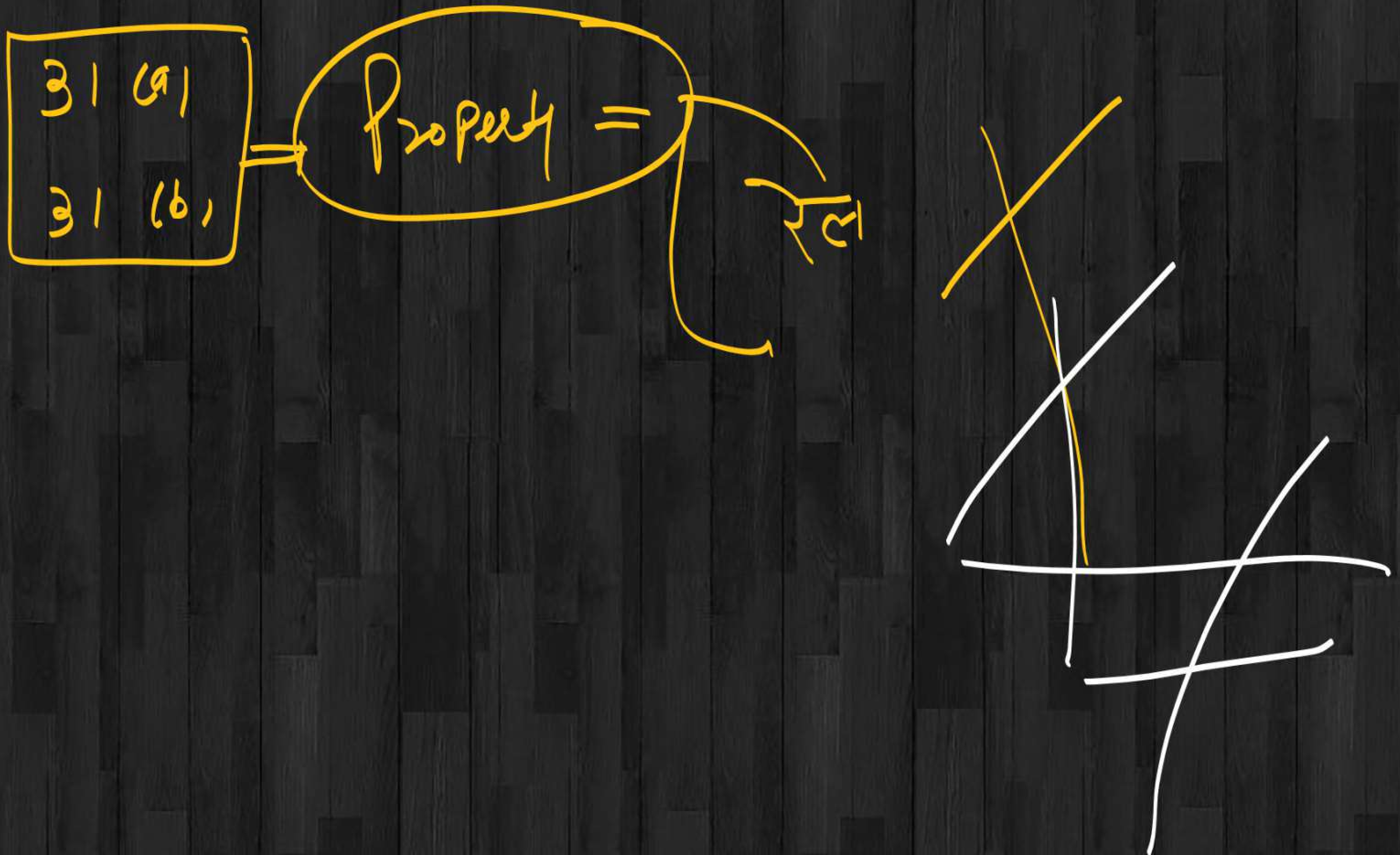
Property =

AMU – पैसा – सरकार
सरकार

AMU
JMI

Note = अभी हाल ही कोर्ट ने AMU – को अल्प

Matter

Jhini – धारा

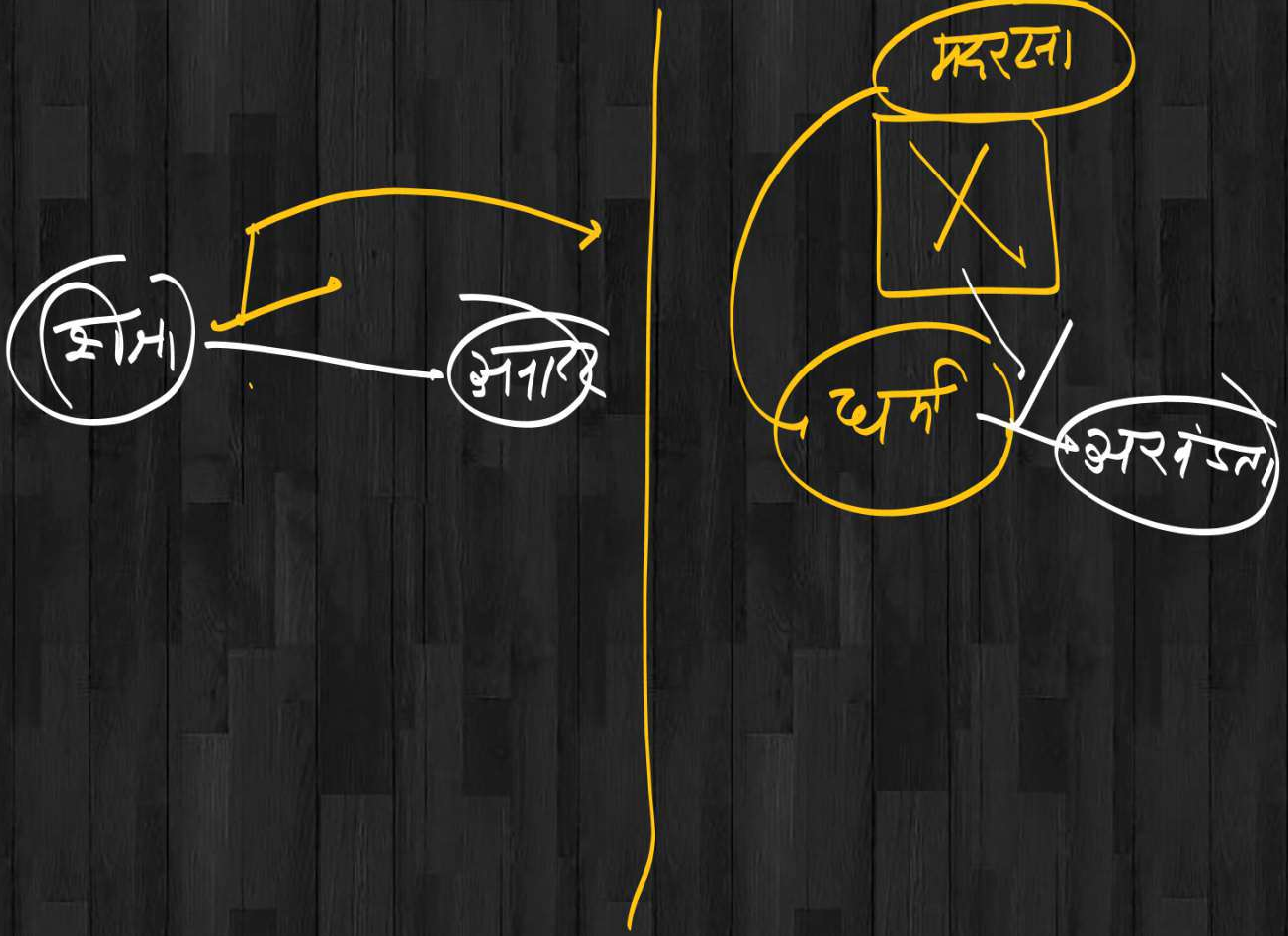
क्षमा
मदरसा
धर्म
अखंडता

30 ⇒

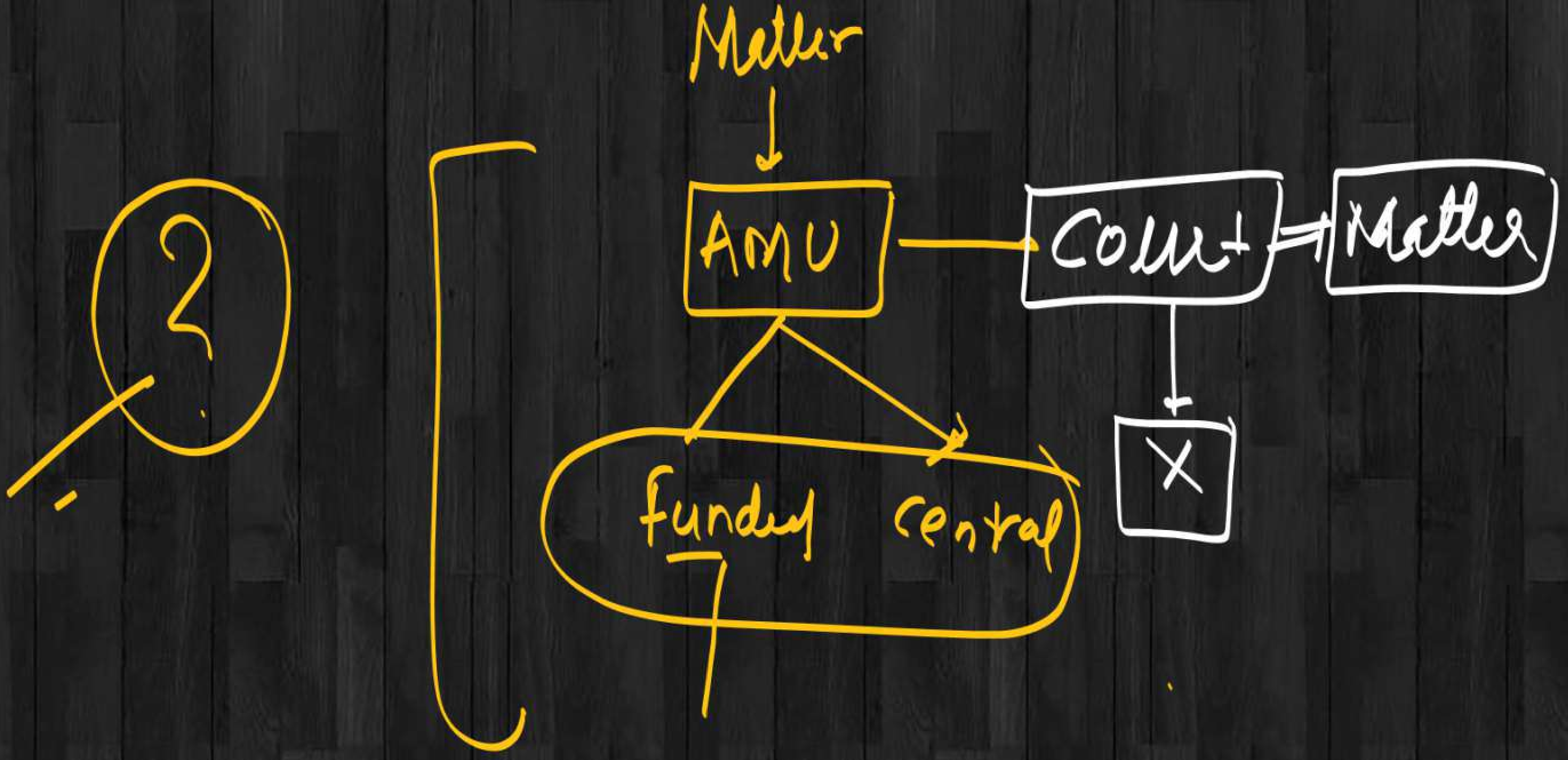

Matter
AMU
Court
Matter
funded
central

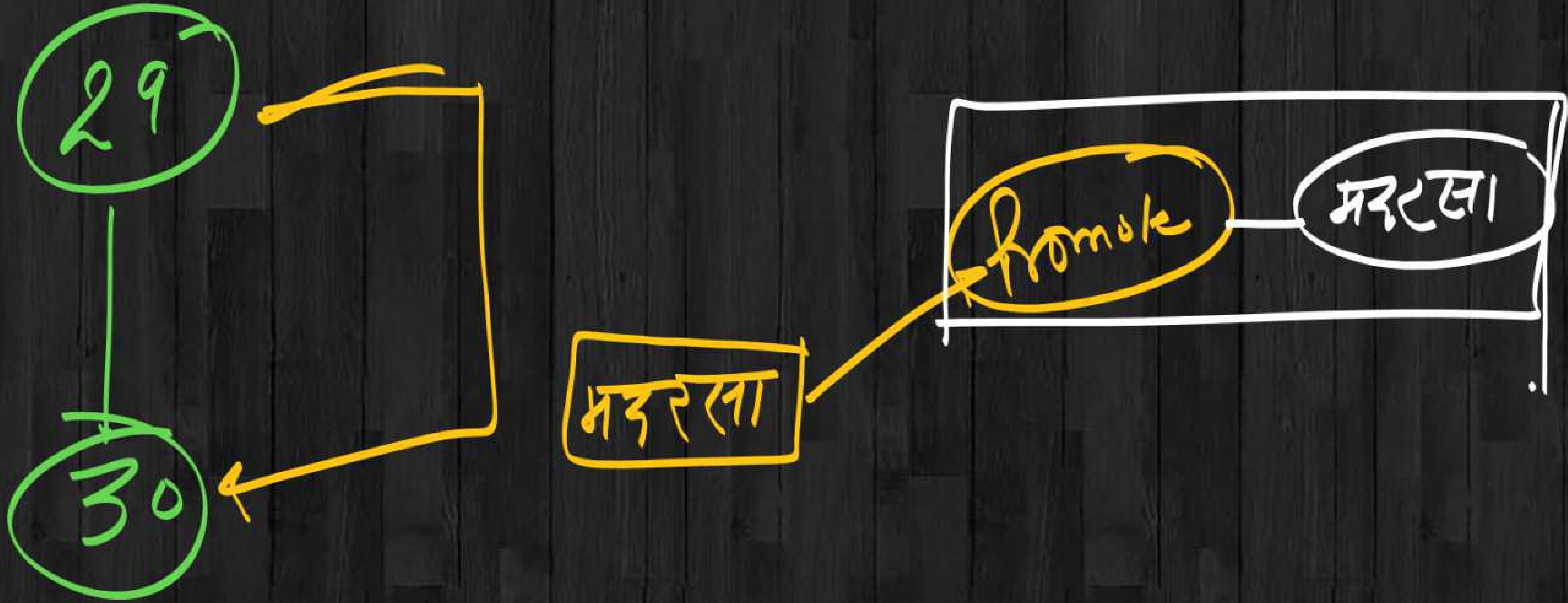
29
30
मदरसा
Promote
मदरसा

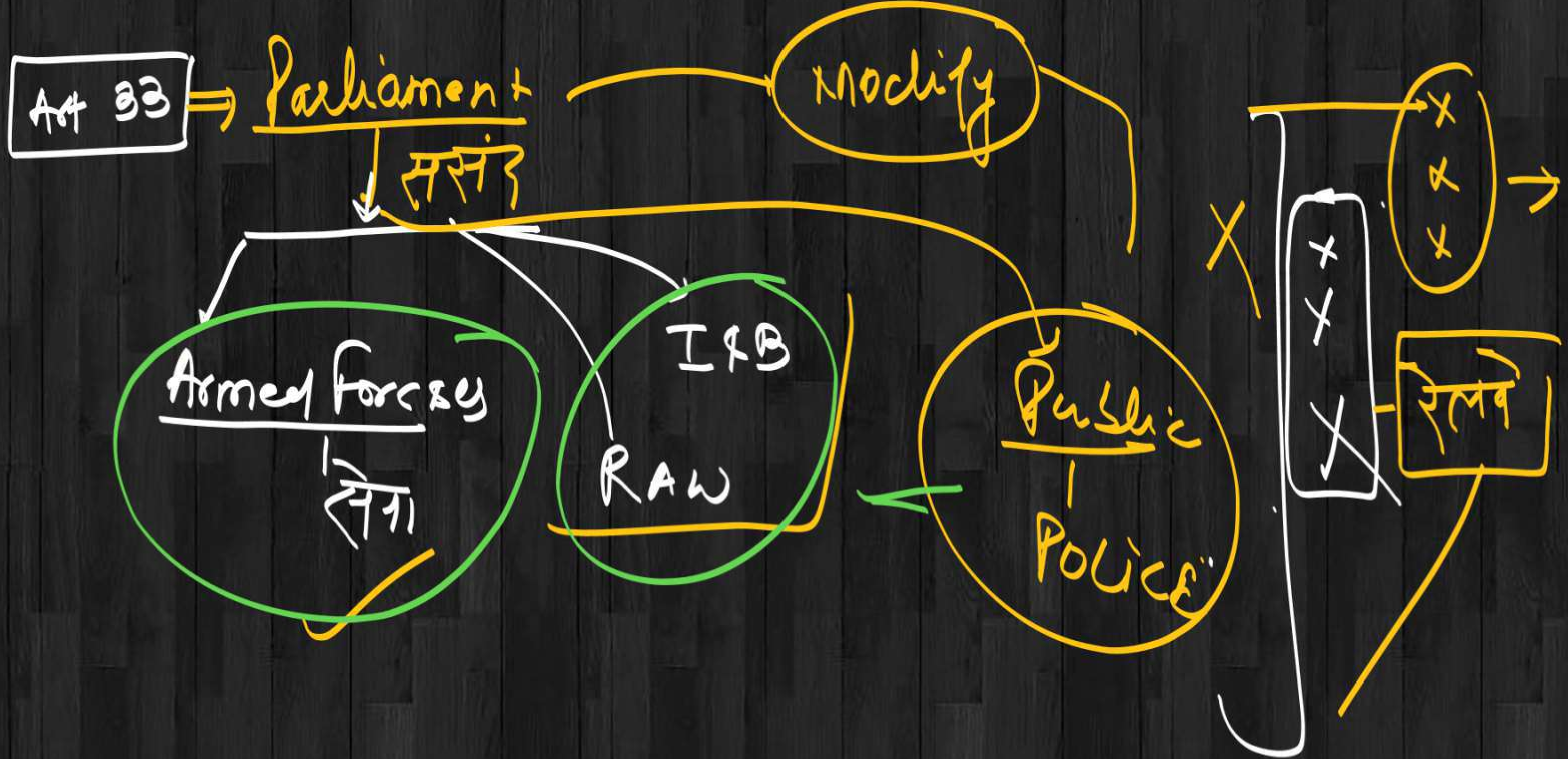

Art 33
Parliament
संसद
modify
Armed Forces
सेना
I&B
RAW
Public
Police
रेलवे

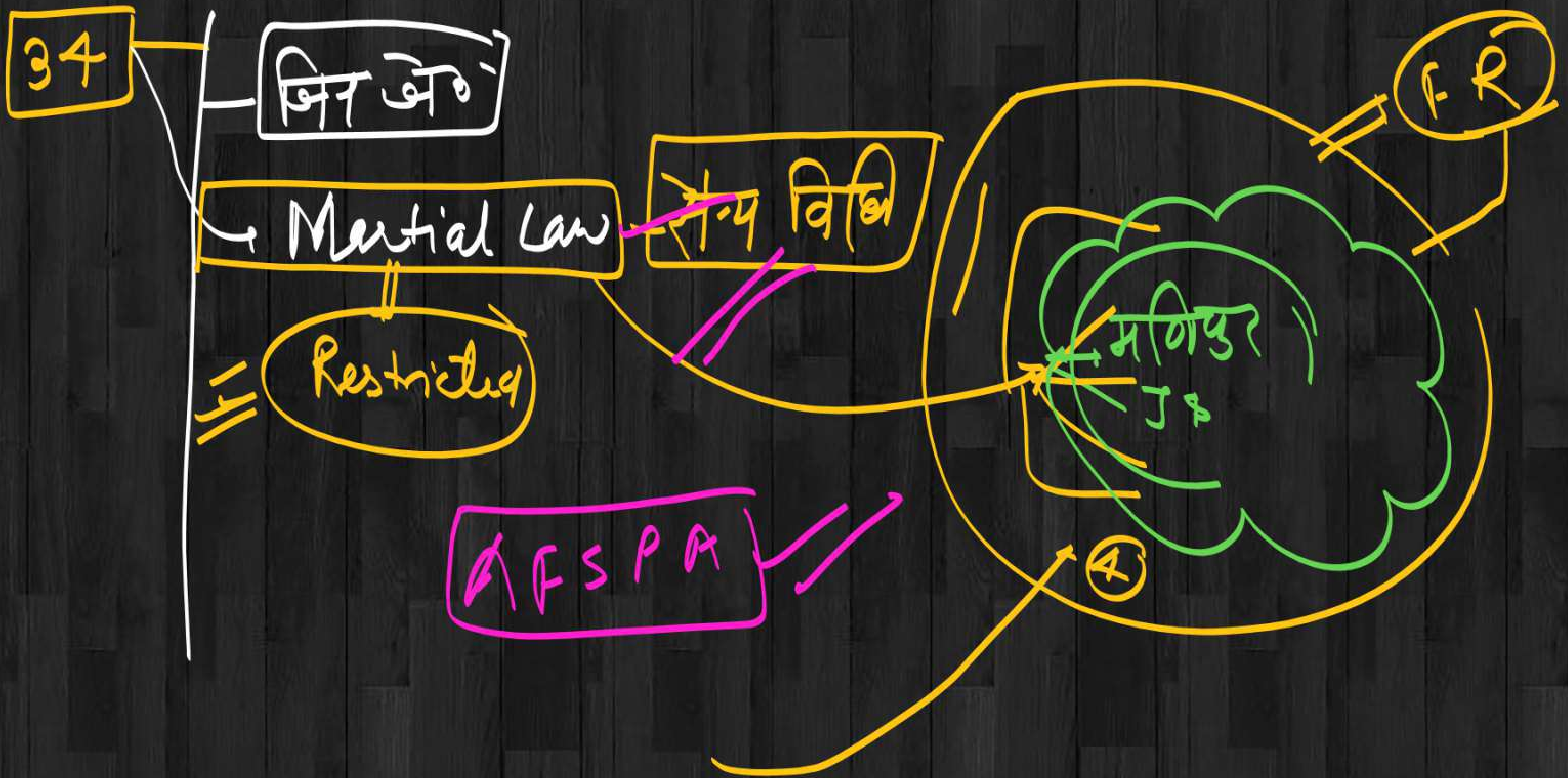

34
मिन ओर
Martial Law
सैन्य विधि
Restricted
AFSPA
मणिपुर
J&K
F.R

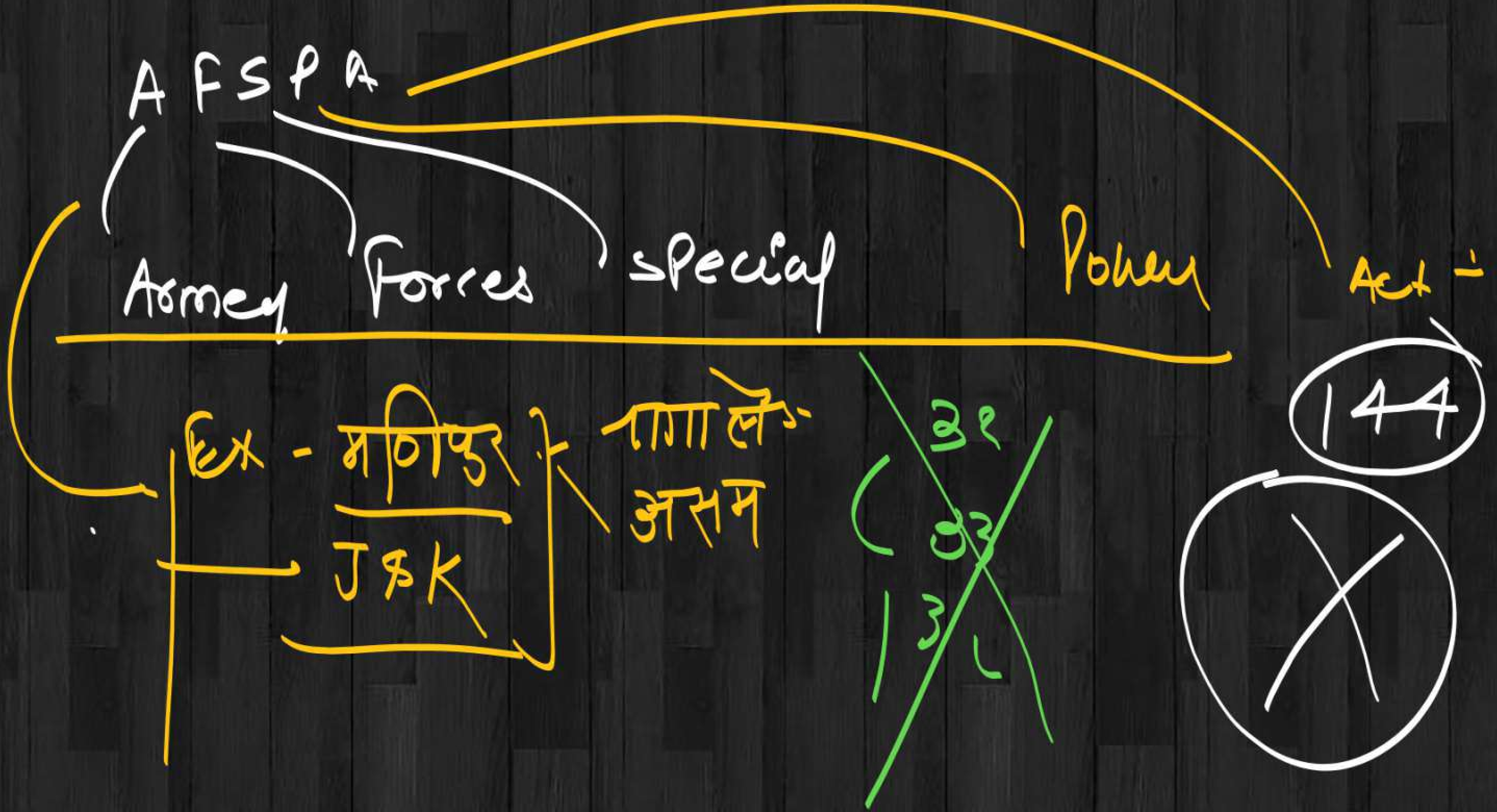
AFSPA
Armey
Forces
special
Power
Act -
144
Ex - मणिपुर
J&K
नागालैंड
असम

Art 35 → Amendment संसोधन

संसद — only Parliament

21(A)

Vesting

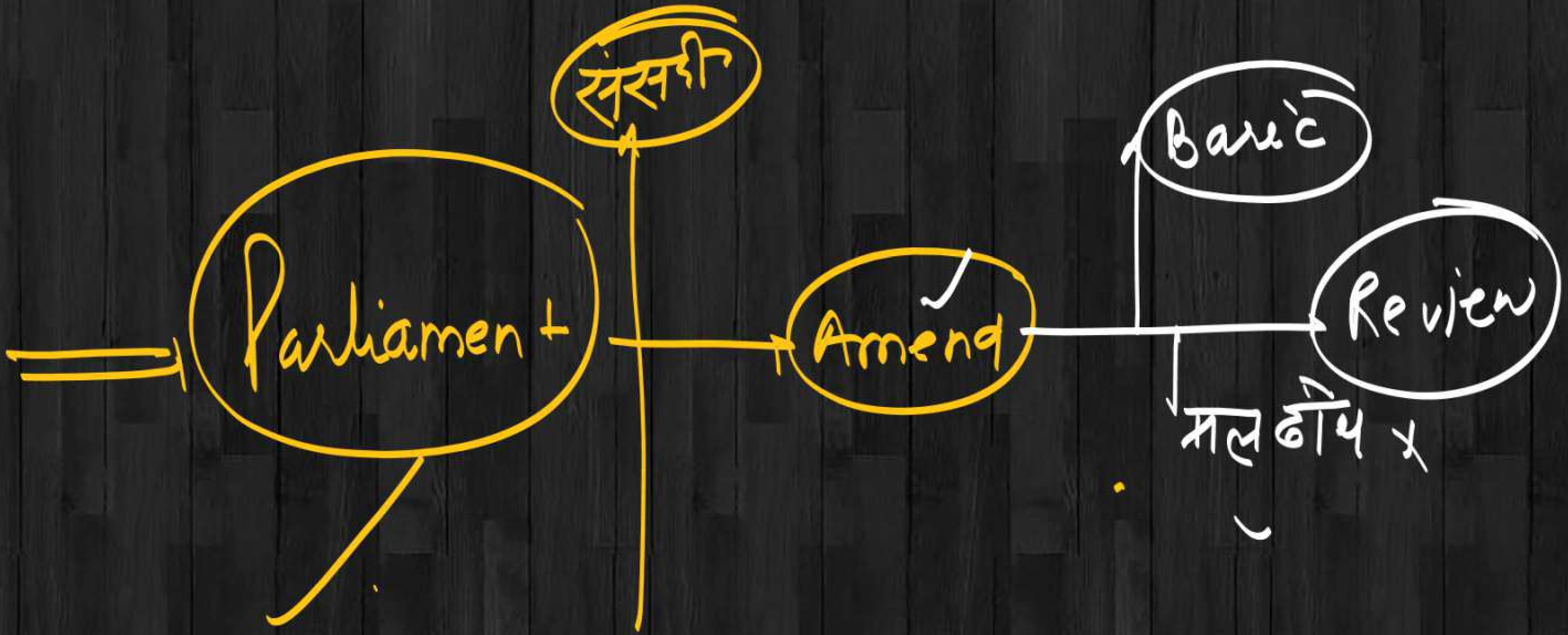
संसदी
Parliament
Amend
Basic
Review

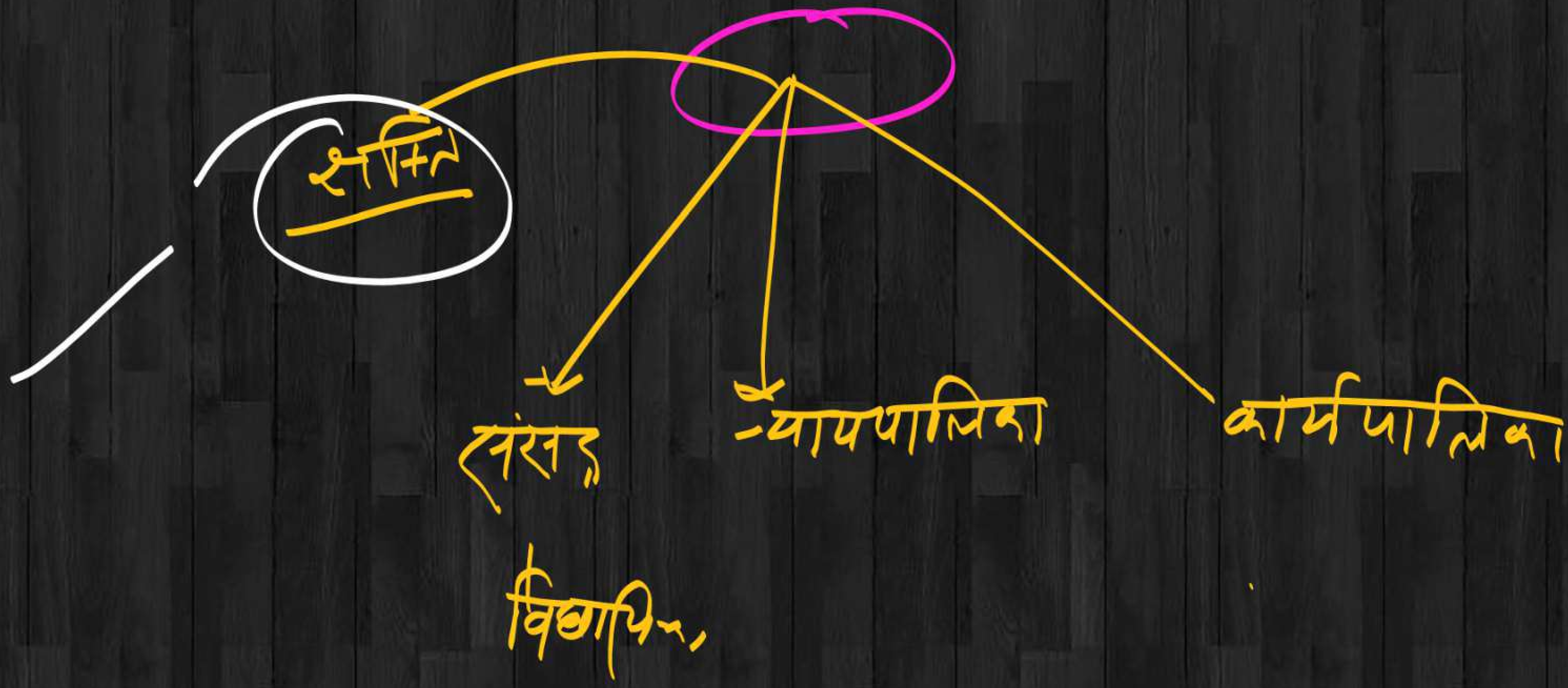
शक्ति
संसद
न्यायपालिका
कार्यपालिका
विधायिका,

(A) = Note =

15, 16, 19, 29, 30 — F.R — FR — नागरिको को प्राप्त — Citizen of I

14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 — नागरिक + गैर नागरिक — Citizen + Non citizen

⇒ आपातकाल

↓

अ352 - राष्ट्रीय

National

Except

→ 20, 21

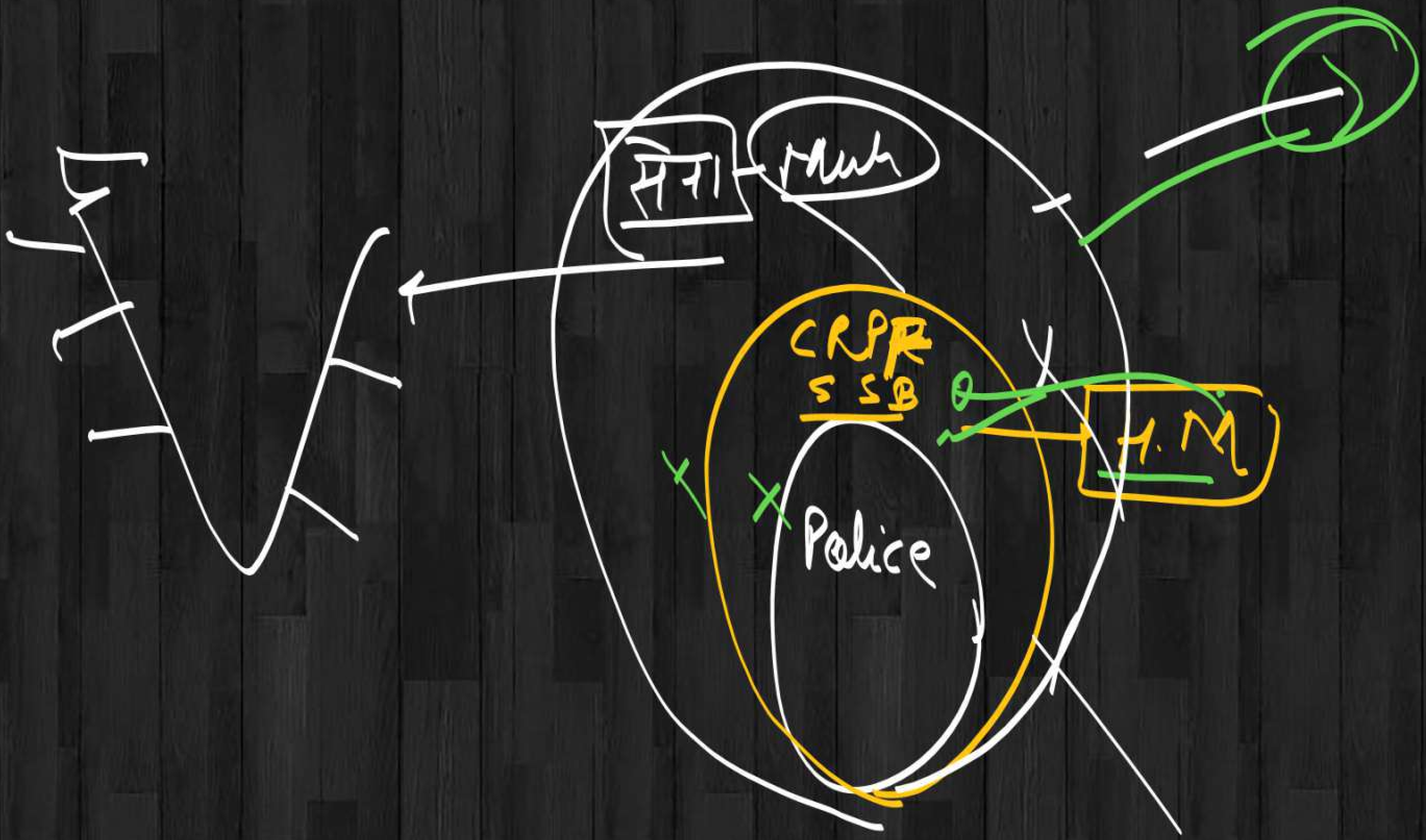

सेना
CRPF
SSB
Police
H.M

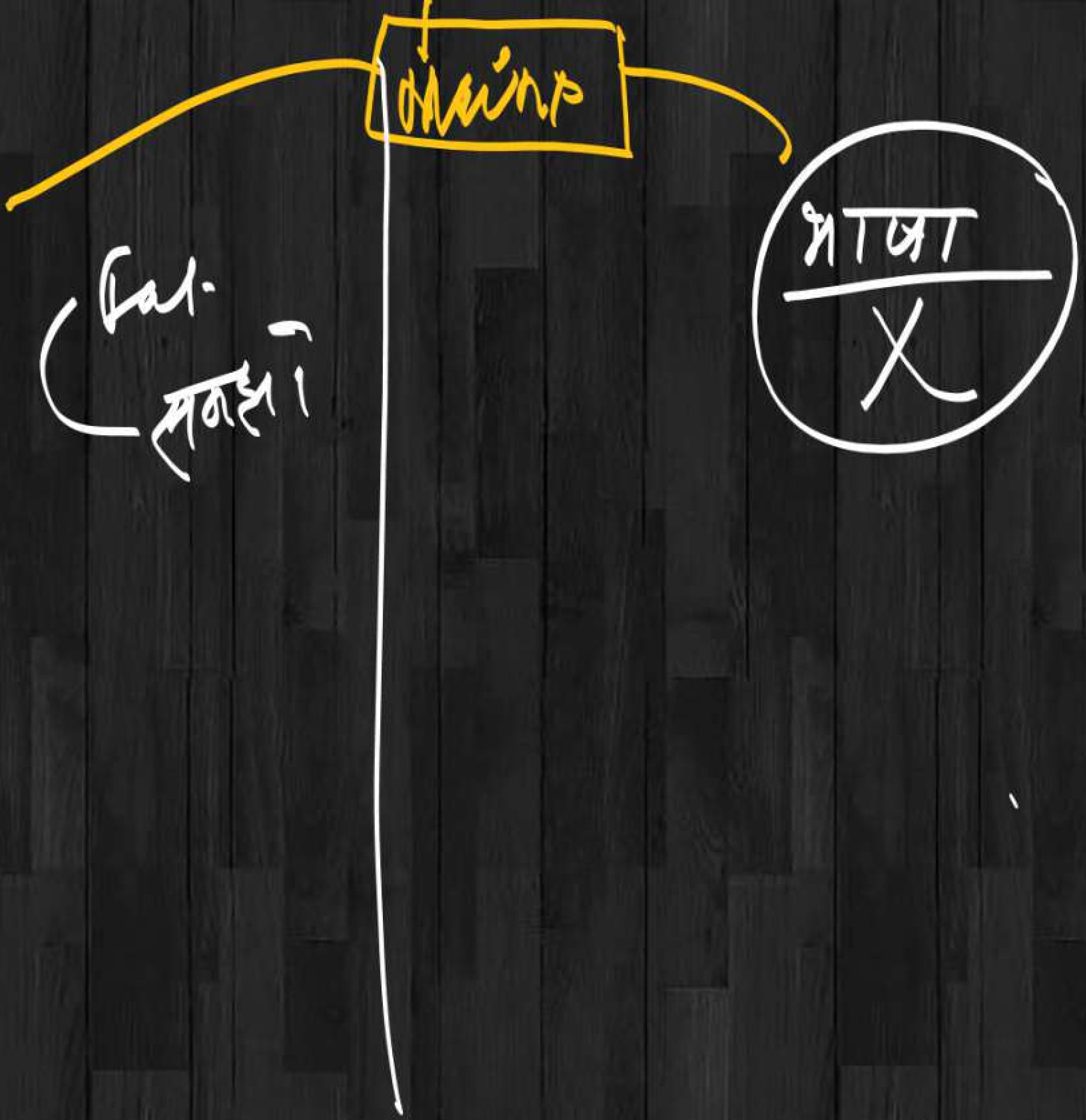
भाषा

भाग = 4 → नीति निर्देशक त.व

[Directive Principles of State Policy]

36 से 51

नीति - Policy

निर्देशों - Direction

आयरलैंड Ireland

- Irish

36-अनु :- "राज्य" → की परिभाषा

अनु 12

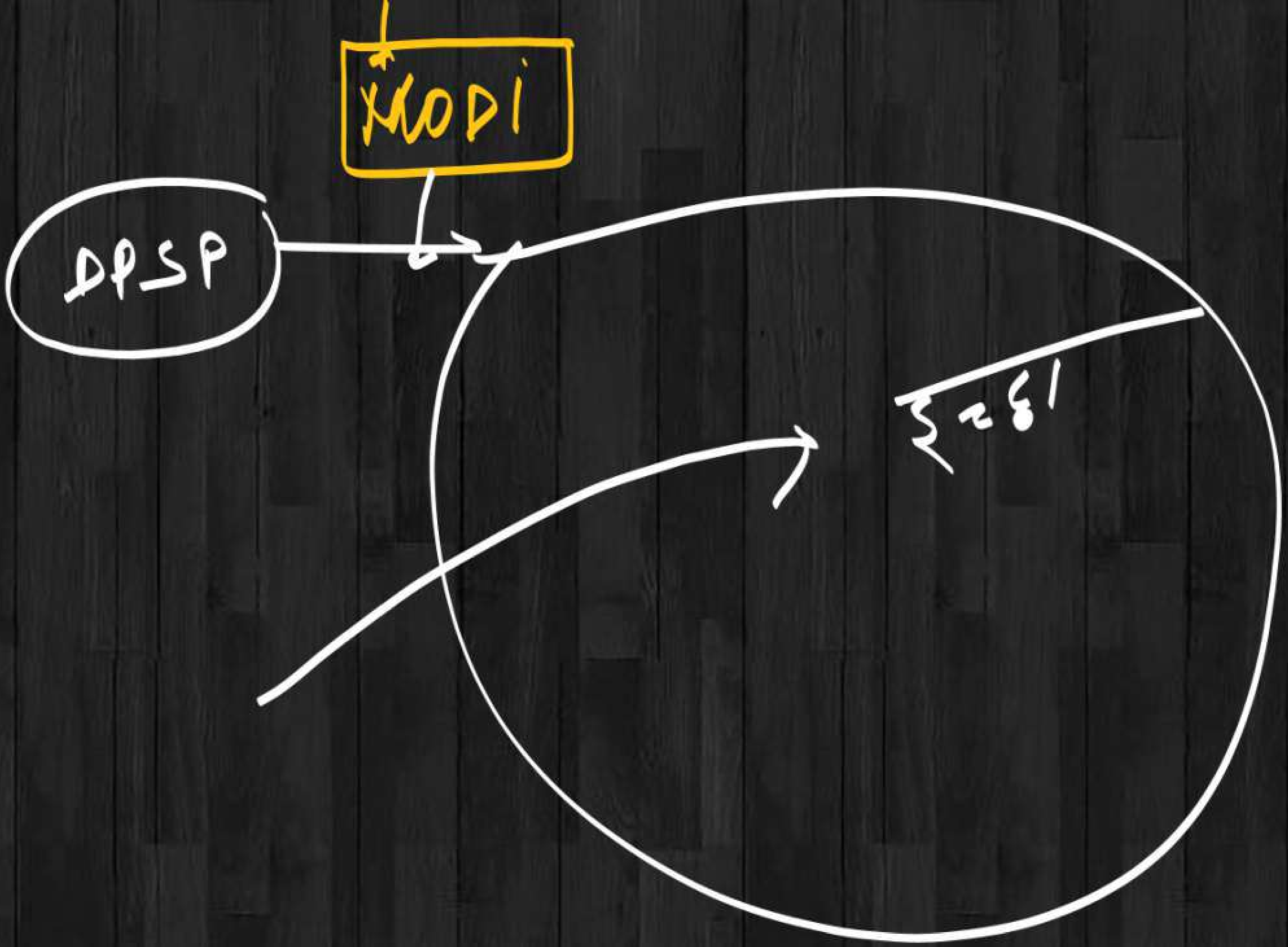
MODI
DPSP

तेज बहादुर

FR

DPSP

A 35

33

नीति – निदेशक तत्त्वों का इतिहास
(History of Directive Principles)

भारतीय संविधान में नीति – निदेशक तत्त्वों का विकास मूल अधिकारों के विकास के साथ ही हो गया था। संविधान सभा के सदस्यों में इस बार पर सहमति बन गई थी कि स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार तो दिये ही जाने चाहिये, साथ ही राज्य ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी की जानी चाहिये जो सामाजिक न्याय के लिये वांछनीय हैं। इन सिद्धांतों को मूल अधिकारों के रूप में दिया जाना तत्कालीन परिस्थितियों में संभव नहीं था। ऐसे अधिकार, जिन्हें तत्काल देना संभव नहीं था, बी.एन. राव की सलाह पर नीति–निदेषक तत्त्वों की श्रेणी में रख दिये गए, ताकि जब सरकारें समक्ष हो जाएँ तब धीरे–धीरे इन उपबंधों को लागू करें। इन्हीं उपबंधों को संविधान के भाग 4 में रखा गया तथा राज्य के नीति–निदेषक सिद्धांत नाम दिया गया।

संविधान के भाग 4 को राज्य के नीति–निदेषक तत्त्व (डी. पी. एस.पी.) शीर्शक दिया गया है। इसके अंतर्गत 36 से 51 तक के अनुच्छेद शामिल हैं। संविधान का यह भाग आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है । इसके माध्यम से संविधान राज्य को बताता है कि उसे सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिये नैतिक दृष्टि से किन पक्षों पर बल देना चाहिये।

निदेषक तत्त्वों का महत्व
(Importance of Directive Principles)

- 'लोक–कल्याणकारी राज्य' की स्थापना
- आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना।
- भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधारः अधिकांष योजनाएँ इससे प्रेरित हैं।
- इसमें संविधान का दर्षन निहित होता है।
- जब कभी न्यायपालिका के सम्मूख कोई संवैधानिक कठिनाई उत्पन्न हुई है, न्यायपालिका ने संविधानन की प्रस्तावना तथा राज्य के नीति–निदेषक तत्त्वों को ध्यान में रखकर संविधान को समझने का प्रयास किया है।

राज्य के नीति–निदेषक सिद्धांत

(Directive principles of state policy)

- अनुच्छेद 36: नीति–निदेषक तत्त्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। इसमें भी राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है।

- अनुच्छेद 37: इस भाग में दिये गए तत्त्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए भी देष के शासन में मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्त्तव्य होगा।

- अनुच्छेद 38: राज्य लोग–कल्याण की अभिवषद्धि के लिये सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।

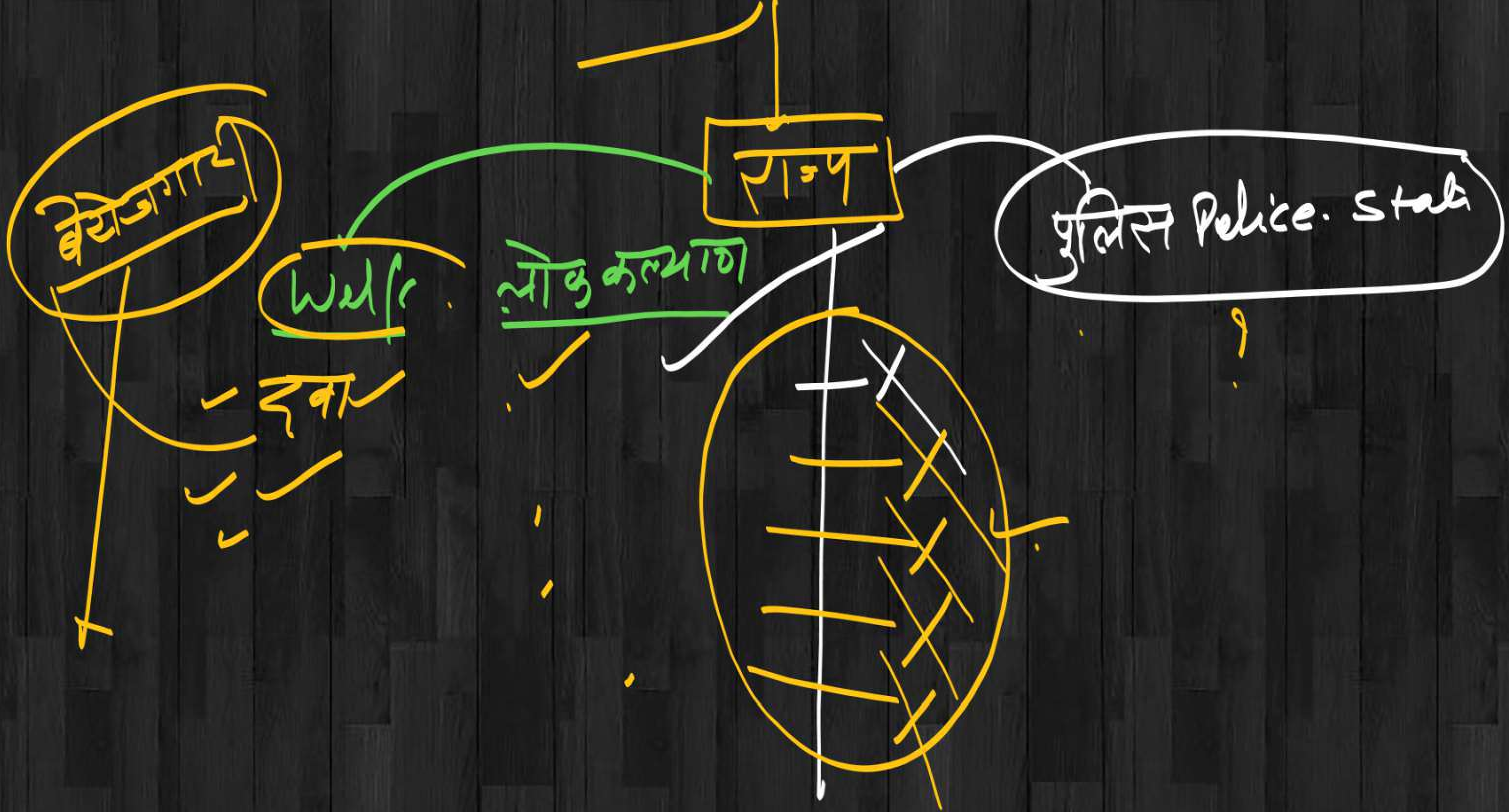
बेरोजगारी
Welf.
लोककल्याण
राज्य
पुलिस Police. State
दवा

- अनुच्छेद 38: राज्य लोग–कल्याण की अभिवर्षद्धि के लिये सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके।

  42 वें संविधान संषोधन, 1976 के माध्यम से नीति–निदेषक तत्त्वों में अनुच्छेद 39 क, 43 तथा 48 को अंतः स्थापना किया गया।

- अनुच्छेद 38 (2) : आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना।

- **अनुच्छेद 39:** राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति–निर्देषक तत्त्व–
  - (क) पुरुशों व स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधान प्राप्त करने का अधिकार।
  - (ख) समाज में भौतिक संधाधनों के स्वामित्व का उचित वितरण।
  - (ग) अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों के अहितकारी कंद्रीकरण का निषेध।
  - (घ) पुरुषों व स्त्रियों दोनों के लिये समान कार्य के लिये समान वेतन।
  - (ड़) पुरुषों व स्त्री श्रमिकों तथा बच्चों को मजबूरी में आयु या शक्ति की दृश्टि से प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना।
  - (च) बच्चों को स्वतंत्र और गरिमा के साथ विकाष का अवसर प्रदान करना और षोशण से बचाना।

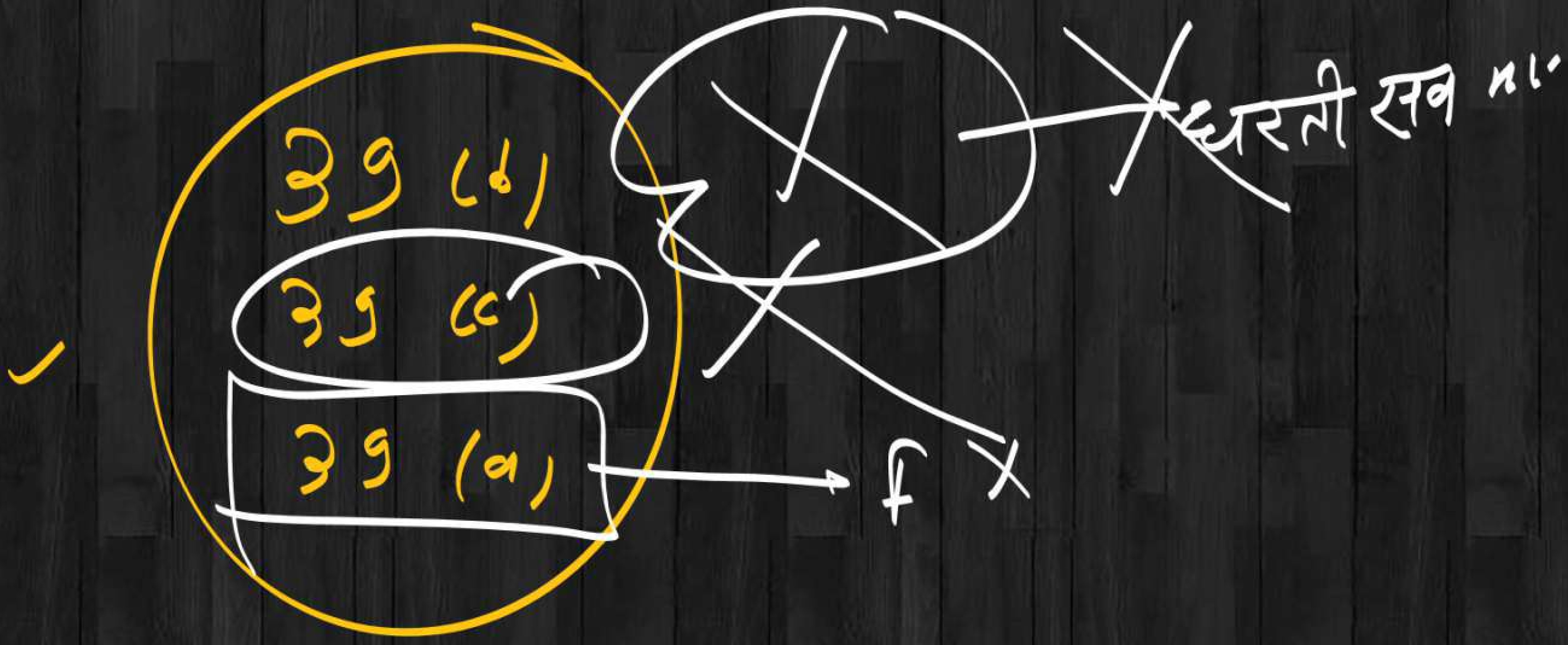

39 (d)
39 (c)
39 (a)
f
धरती सब

1 Politi

Const

Ethn

Rule - Func

Unity

Cu

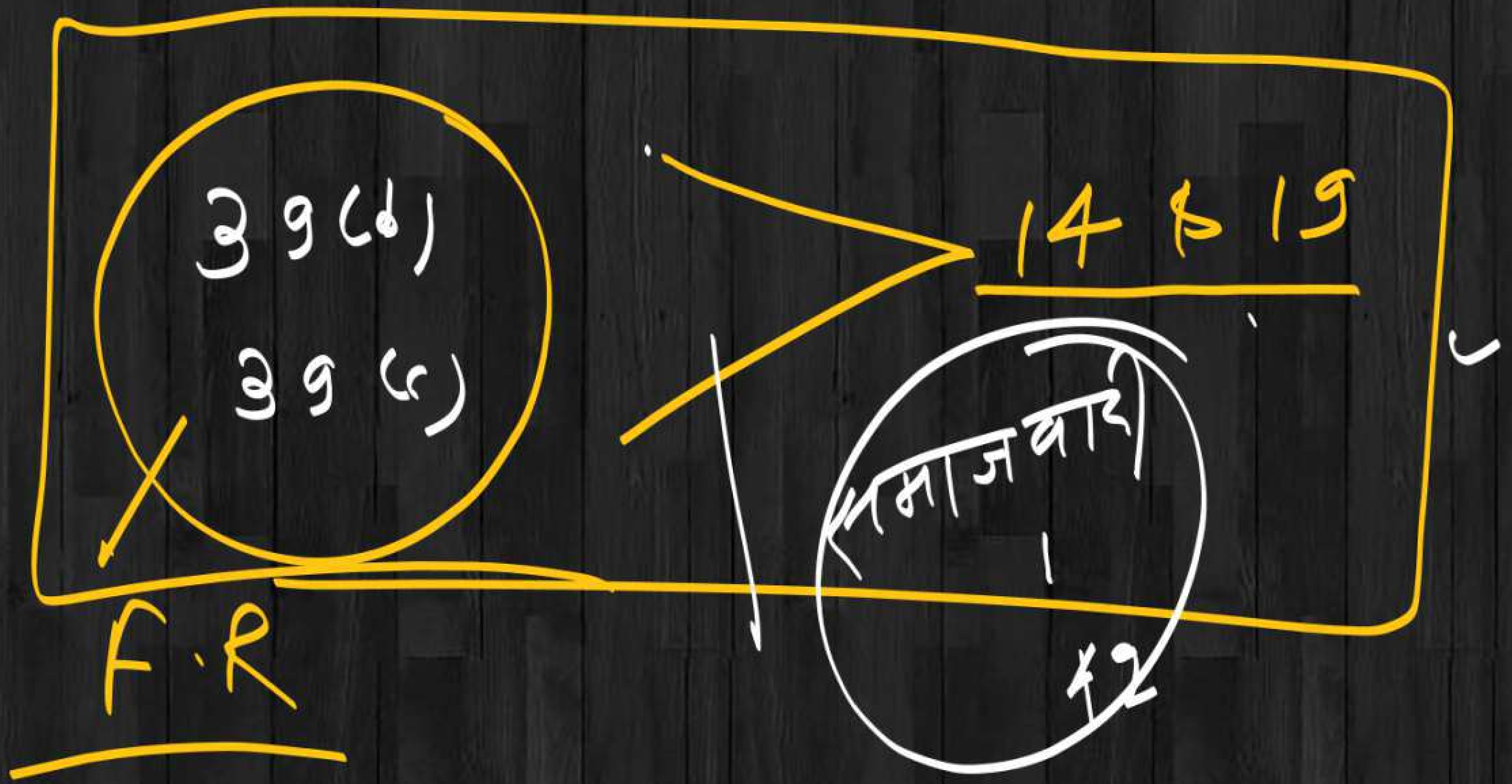
39(b)
39(c)
F.R
14 & 19
समाजवादी
42

चाहिए

Should

चाहता है

F.R

39 (a)
(b)
(c)
(d)
39 (A)
39 (B)

- अनुच्छेद 39 क (समान न्याय और निःषुल्क विधिक सहायता): राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधि तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो तथा आर्थिक या किसी भी अन्य आधार पर नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाएँ। यह विधिक सहायकता निःशुल्क होगी।

39(A) :- समान न्याय एवं निशुल्क विधिक

39(A)

free legal aid — फ्री

NALSA - राष्ट्रीय

SALSA

DALSA

Act

NALSA - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

(National legal Service Authority) - 1987

कारा

SALSA State = राज्य

DALSA - District - जिला

1994 - 1995

- अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायतों का गठन):
  राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिये कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त षासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हों।

Imp

Organisations of village Panchayat -

73 = 1992

74 - 1992

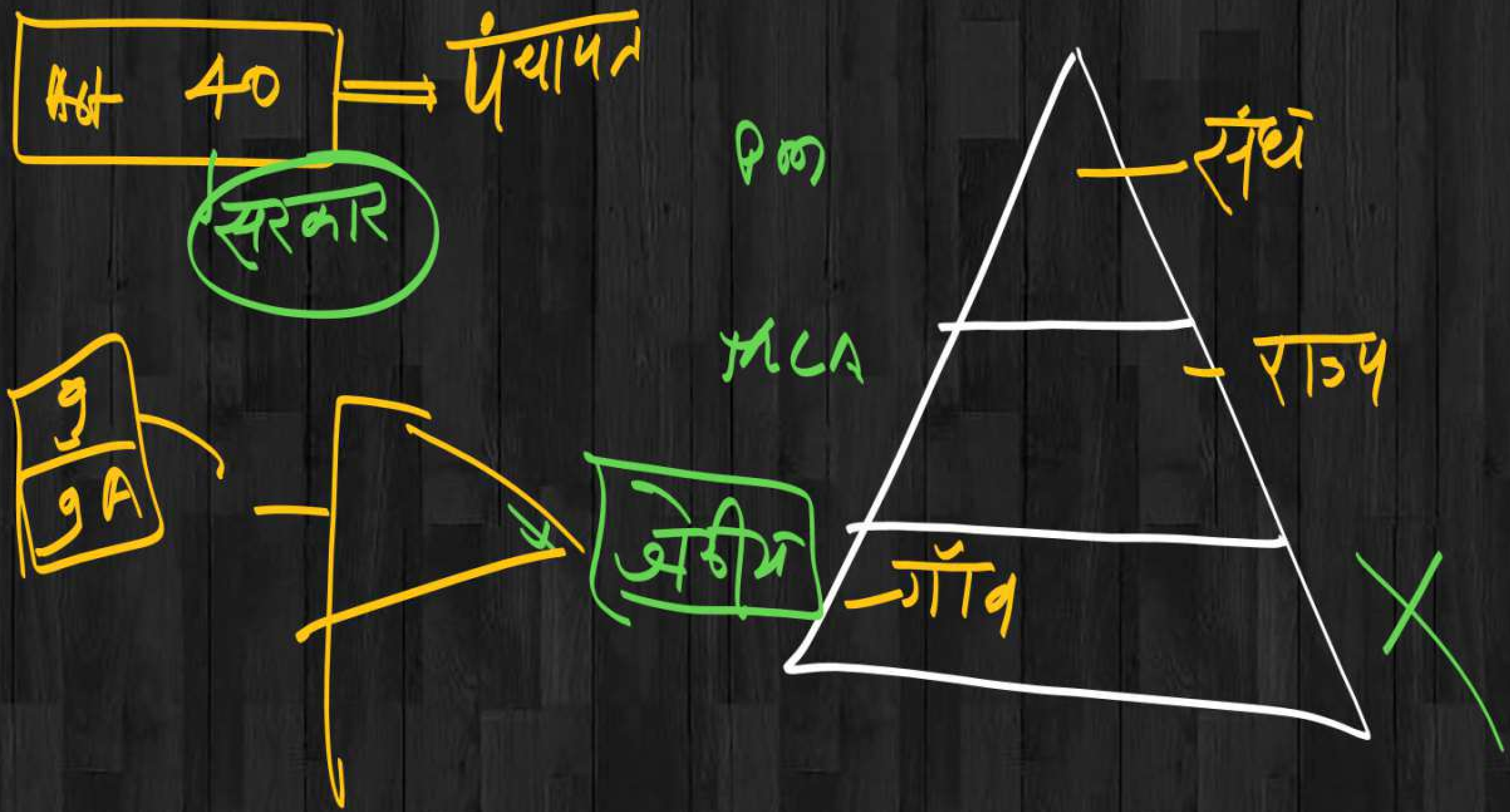

40
पंचायत
सरकार
PM
MLA
संघ
राज्य
गाँव
9
9A

- अनुच्छेद 41 (कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक–सहायकता पाने का अधिकार): राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक–सहायता पाने के अधिकार का प्रभावी उपबंध करेगा।

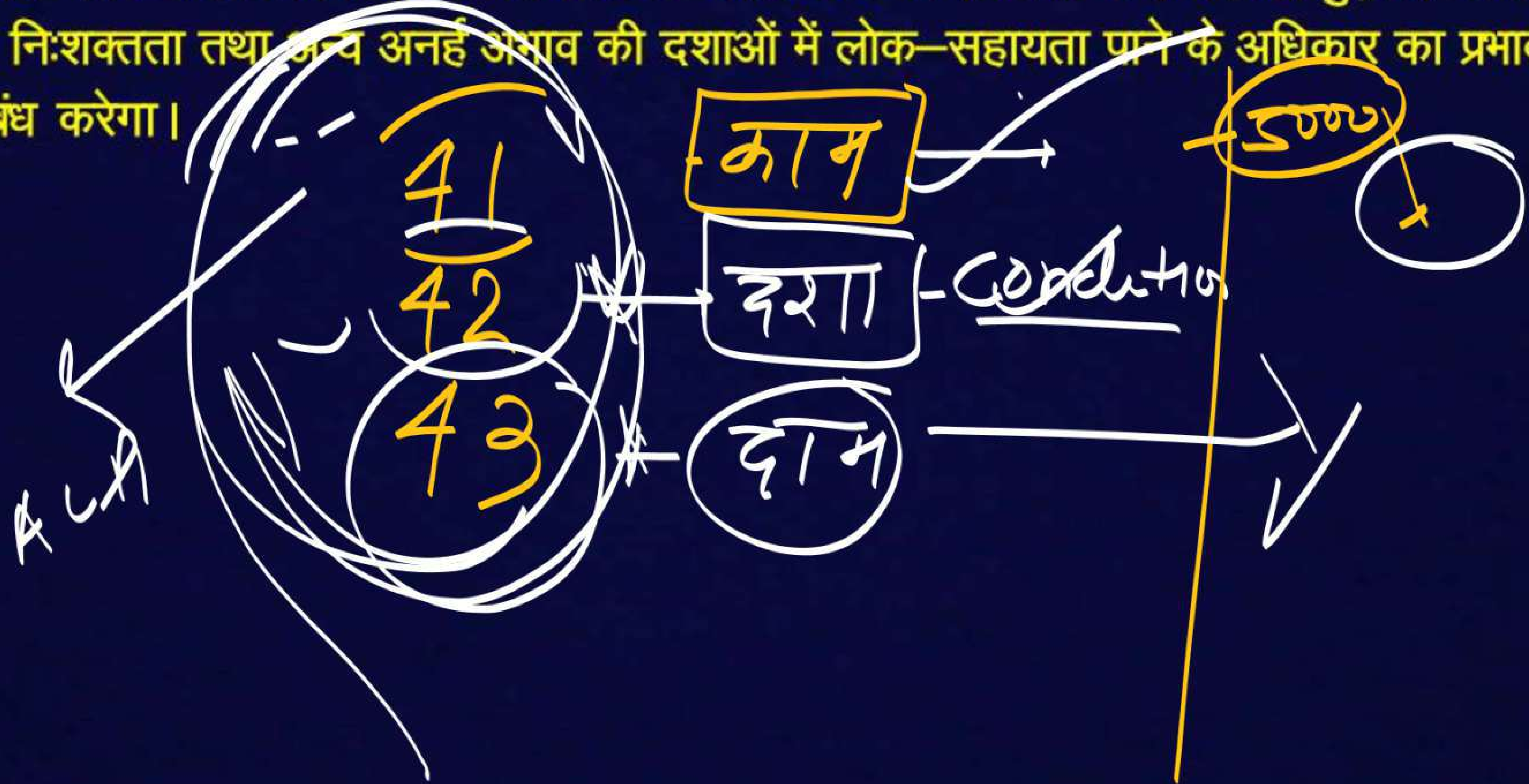

- अनुच्छेद 42 (काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं कमा तथा प्रसूति सहायता का उपबंध):

42

X

Good Condition for Work

and

Maternity Benifit (Relief)

अनुच्छेद 43 : कर्मकारों के लिये निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर व अवकाश की व्यवस्था करना और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना।

43 - निर्वाह मजदूरी ≠ Living wages

For.

41 → काम — MANREGA

42 — दशा — प्रसूति — Hr

43 - दाम

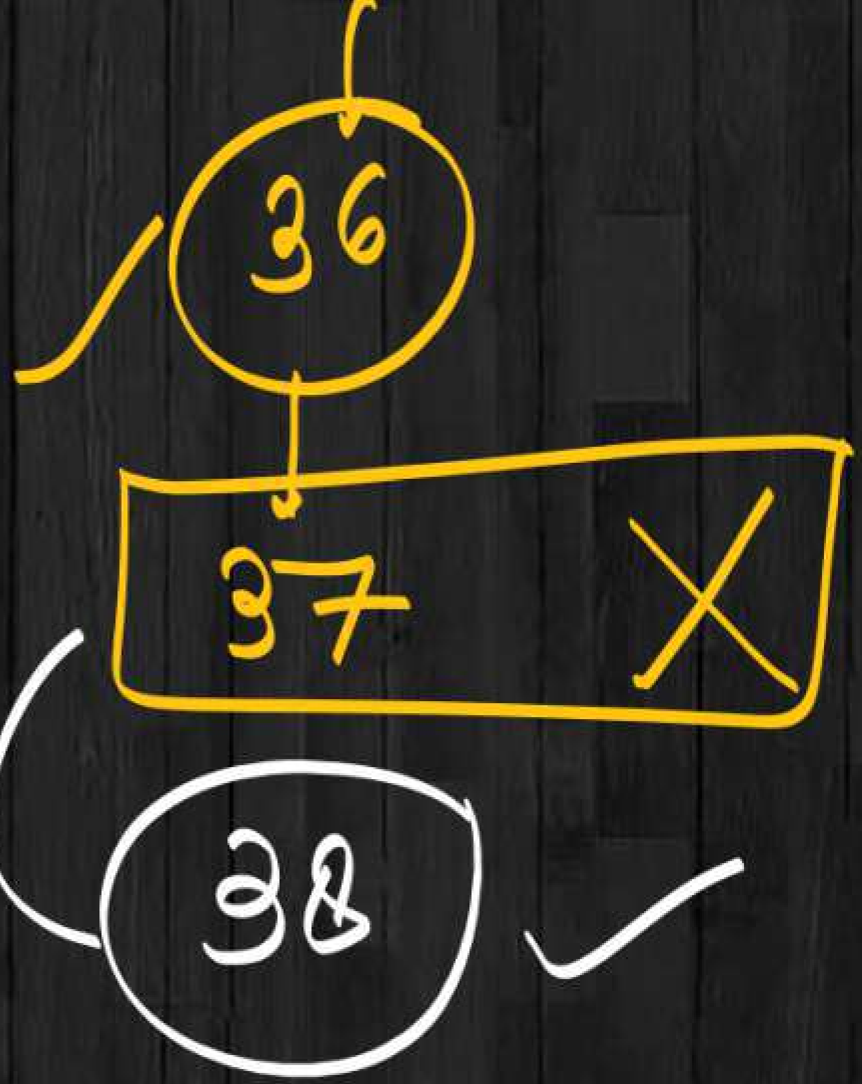
36
37
38

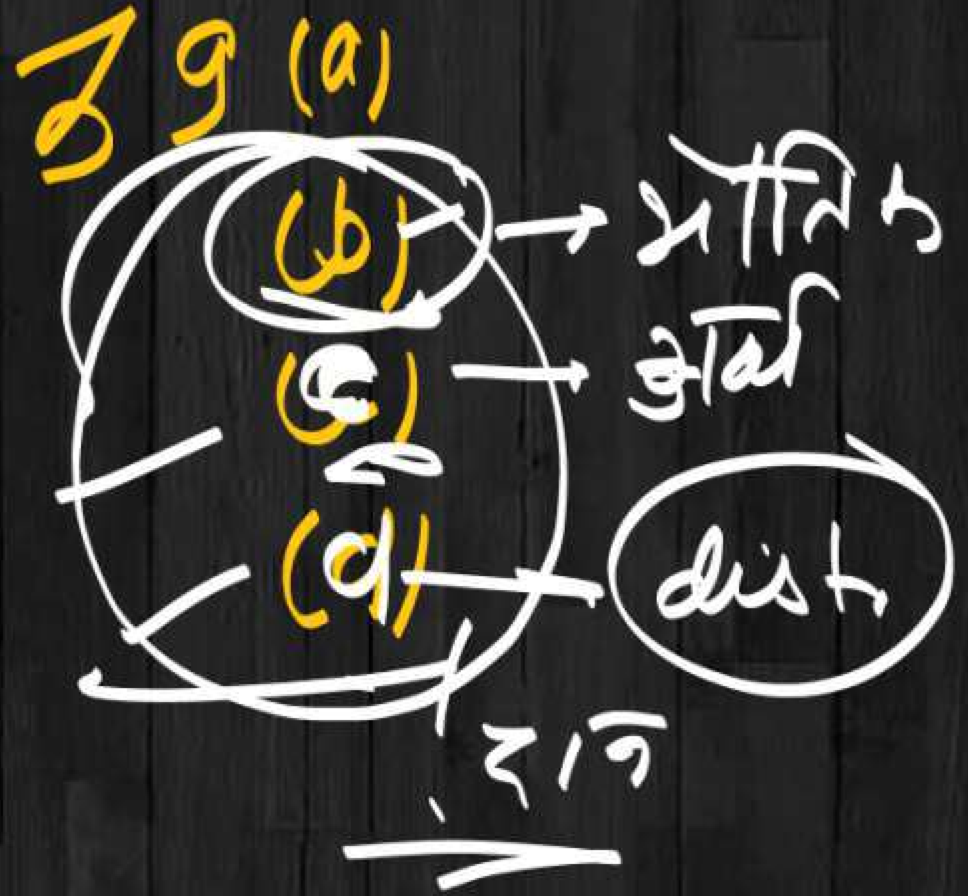

(a)
(b)
(c)
(d)
dist

39 (A) — 42

//

40

41 — काम

42 राज

43 - राम

44 ⇒ [एक समान नागरिक संहिता
Uniform civil code]

- अनुच्छेद 45: शिशुओं (प्रारंभिक शैशवावस्था) की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करना ।

- अनुच्छेद 46: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवशद्धि करना और हर तरह के शोशण व सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना ।